पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2026 ई0 (श्रावण 17, 1948 शक सम्वत्) [संख्या–32

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	511–522	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	271–326	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01–03	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	355–366	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग)

14 जुलाई, 2026 ई0

संख्या–919/XXXI(15)G/2026-13(सा0)/2025–राज्यपाल, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा भारत की जनगणना, 2027 के दूसरे चरण के पूर्व–परीक्षण के संचालन की अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में निम्नानुसार पुनःप्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जून, 2026

का.आ. 3472 (अ).– केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क सपठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यो एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की जनगणना, 2027 के दूसरे चरण के पूर्व–परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार, निम्नानुसार करती है:–

(i) जनसंख्या गणना का पूर्व–परीक्षण चयनित नमूना क्षेत्रों में 6 जुलाई, 2026 से 18 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा, इसका पुनरीक्षण दौर 19 जुलाई, 2026 से 20 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा।

(ii) 1 जुलाई, 2026 से 5 जुलाई, 2026 तक स्व–गणना के लिए विकल्प होगा।

[(फा.सं. 9/8/2025–सीडी (मेन)]
मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 919/XXXVI(15)/2026-13(सा0)/2025 dated July 14, 2026 for general information:

July 14, 2026

No. 919/XXXVI(15)/2026-13(सा0)/2025--In exercise of the powers conferred under rule 8(i) of the Census Rules 1990, the Governor is pleased to allow to republish the notification issued by the Central Government, for conduct of Pre-test of Second phase of Census of India, 2027, in the official gazette of the State of Uttarakhand as follows namely:-

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office Of Registrar General, India)

NOTIFICATION
New Delhi, the 27th June, 2026

S.O. 3472 (E).- In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby extends the provisions of the said Act for conduct of Pre-test of second phase of Census of India, 2027 in the States and Union territories, as under:-

i) The Pre-test of Population Enumeration in selected sample areas shall be conducted from 6th July, 2026 to 18th July, 2026, with a revisioinal round from 19th July, 2026 to 20th July, 2026.

ii) There shall be an option for self-enumeration from 1st July, 2026 to 5th July, 2026.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]
MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner, India

By Order,

ANAND BARDHAN,
Chief Secretary.

खेलकूद विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई, 2026 ई0

संख्या 637 / VI-3 / 2026–34(13)2026–चूंकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;

और चूंकि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से परामर्श के उपरांत अपने पत्र संख्या 13(4)/2020-EG-II(Pt.), दिनांक 10 अप्रैल, 2026 द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के खेल विभाग (जिसे आगे "उक्त विभाग" कहा गया है) को, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु, आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान की है तथा उक्त नियमावली के नियम 5 सपठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अधीन इसकी अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की है;

और चूंकि खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से खेल विभाग की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु खिलाड़ियों/निवासियों तथा प्रशासनिक कार्यों तथा खेल विभाग के कार्मिक/सपोर्ट स्टॉफ के प्रयोजनार्थ (जिसे आगे "उक्त प्रयोजन" कहा गया है), आधार प्रमाणीकरण उक्त नियमावली के नियम 3 के उप–नियम (1) के अनुसार किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन हेतु आधार प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और उक्त विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण केवल उपयोगकर्ता डेटा के सत्यापन तथा डुप्लिकेट प्रविष्टियों को रोकने के उद्देश्य से किया जाएगा (जिसे आगे "उपयोग प्रकरण" कहा गया है);

अतः, अब उक्त नियमावली के नियम 5 सपठित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में, खेल विभाग निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात :–

1. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विभाग प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक होगा। विभाग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी प्रदान करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण से इंकार करने अथवा प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात :–

(क) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड
(ख) पासपोर्ट
(ग) मतदाता पहचान पत्र
(घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी।

3. पूर्व जारी अधिसूचना संख्या–602/VI-3/2026–34(13)2026, दिनांक 19 जून, 2026 एतद्द्वारा अधिक्रमित समझी जायेगी।

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 637/VI-3/2025-34(13)2026,** Dehradun dated July 10, 2026 for general information:

NOTIFICATION

July 10, 2026

No. 637/VI-3/2026-34(13)2026--Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. **13(4)/2020-EG-II(Pt.)** , dated 10th of April 2026, to the **Department of Sports** (herein after referred to as the said, department, **Government of Uttarakhand** (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020

(hereinafter referred to as the said rules).that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for athletes/residents for availing services Sports Department and department of employees/support staff for administrative purposes, through Portal of Sports Department (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and For the said purpose, Aadhaar authentication shall be carried out on a purely voluntary basis, and the said department shall conduct Aadhaar authentication solely for the purpose of verifying user data and preventing duplicate entries (hereinafter referred to as the "Use Case");

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Department of Sports hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis. The Department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —
(a) Permanent Account Number (PAN) Card
(b) Passport
(c) Voter Identity Card
(d) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

3. The previously issued Notification No-602/VI-3/2026–34(13)2026, Dated 19 June, 2026 shall hereby deemed to be superseded.

By Order,

AMIT KUMAR SINHA,
Special Principal Secretary
Department of Sports.

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

27 मई, 2026 ई0

संख्या I/399557/2025 (E-34564)–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये "उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010" में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: अर्थात्:–

उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम–2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) "आवेदक की आय समस्त स्रोतों से रू0 3000.00(रू0 तीन हजार) प्रतिमाह से अधिक न हो।"	(ख) "आवेदक की आय समस्त स्रोतों से रू0 6000.00(रू0 छः हजार) प्रतिमाह से अधिक न हो।"

नियम 3 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. "मासिक पेंशन की धनराशि रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार) से अधिक नहीं होगी। यह धनराशि शुद्ध(नेट) होगी और इस पर कोई महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।"	3. "मासिक पेंशन की धनराशि रू0 6000.00 (रू0 छः हजार) से अधिक नहीं होगी। यह धनराशि शुद्ध(नेट) होगी और इस पर कोई महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।"

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के खण्ड (क) के उपखण्ड (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपखण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(5) "यदि किसी समय पेंशन की राशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से पेंशनर की मासिक आय रू0 3000.00 (रू0 तीन हजार) से अधिक बढ़ जाती है। (आय में अभिवृद्धि की सूचना तुरन्त देने के लिए पेंशनर बाध्य होगा)।"	(5) "यदि किसी समय पेंशन की राशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से पेंशनर की मासिक आय रू0 6000.00 (रू0 छः हजार) से अधिक बढ़ जाती है। (आय में अभिवृद्धि की सूचना तुरन्त देने के लिए पेंशनर बाध्य होगा)।"

आज्ञा से,

युगल किशोर पन्त,
सचिव।

In pursuance of the clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the English translation of Notification **No. I/399557/2025(E-34564),** dated May 27, 2026 for general information:

NOTIFICATION

Miscellaneous

May 27, 2026

No. I/399559/2025(E-34564)--In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, the governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Monthly Pension to Old and destitute Artists and Writers Rules, 2010, namely:--

The Uttarakhand Monthly Pension to Old and destitute Artists and Writers (Amendment) Rules, 2026

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Monthly Pension to Old and destitute Artists and Writers (Amendment) Rules, 2026. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Rule 2	2. In Rule 2 of the Uttarakhand Monthly Pension to Old and destitute Artists and Writers Rules, 2010, (hereinafter referred to as the Principal Rules) for the existing clause (b) As set out in column-1 below, the clause As set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing clause	Column-2 Clause hereby substituted
(b)"The income of the applicant from all sources should not exceed Rs.3000.00 (Rupees three thousand) per month."	(b)"The income of the applicant from all sources should not exceed Rs. 6000.00 (Rupees six thousand) per month."

Amendment of Rule 3

3. In the principal rules for the existing rule 3 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Rule	Column-2 rule hereby subsituted
3."The monthly pension amount shall not exceed ₹3,000.00 (Rupees three thousand). This amount shall be Gross(net) and shall not be subject to any dearness allowance or other allowances."	3. The monthly pension amount shall not exceed ₹6,000.00 (Rupees six thousand). This amount shall be Gross(net) and shall not be subject to any dearness allowance or other allowances.

Amendment of Rule 9

4. In the principal rules, for existing subclause (5) of clause (a) of rule 9 as set out in column 1 below, the subclause set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing subclause	Column-2 Subclause hereby substituted
(5) If at any time the monthly income of the pensioner from sources other than the pension amount exceeds Rs. 3000.00 (Rupees three thousand). (The pensioner shall be obliged to report the increase in income immediately).	(5) "If at any time the monthly income of the pensioner from sources other than the pension amount exceeds Rs. 6000.00 (Rupees six thousand). (The pensioner shall be obliged to report the increase in income immediately)."

By Order,

YUGAL KISHORE PANT,

Secretary.

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना / स्थानान्तरण

07 जुलाई, 2026 ई0

संख्या 735 / 2026 / 10(100/XXVII(8)/2022–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानान्तर्गत स्थानान्तरण वर्ष 2026–27 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा सम्यक विचार–विमर्शोपरान्त की गई संस्तुति के आलोक में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी–"क" के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित कार्यालय / स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

• संयुक्त आयुक्त, राज्य कर की सूची :

क्र. स	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल / कार्यालय	प्रस्तावित तैनाती स्थल / कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रवीण कुमार	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून	यथावत	मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका–304/2025 ठा. रणवीर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 24.07.2025 को पारित आदेश के द्वारा संयुक्त आयुक्त ग्रेड–1 के पद पर की गई पदोन्नति को मा0 न्यायालय द्वारा स्थगित (Stay) कर दिया गया है। इस कारण संयुक्त आयुक्त ग्रेड–1 के पद की वर्तमान स्थिति(Status) स्पष्ट न होने तथा क्षेत्राधिकार के चिन्हांकन(Juridiction) का अंतिम रूप से निर्धारण (Finalise) नही होने के दृष्टिगत उक्त पर विचार नही किया गया।

• उपायुक्त,राज्य कर की सूची :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल / कार्यालय	प्रस्तावित तैनाती स्थल / कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नेहा मिश्रा	अपर आयुक्त (ऑडिट विंग) राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त(क0नि0)–02 राज्य कर, हरिद्वार	03 वर्ष / धारा–17(ख)(एक)के अन्तर्गत अनुरोध ग्राहय योग्य है।
2	श्री राम लाल	उपायुक्त (क0नि0)–3, राज्य कर, रूद्रपुर	उपायुक्त(क0नि0)–03 राज्य कर, रूड़की	3 वर्ष
3	श्री अजय विरथरे	उपायुक्त(वि0अनु0शा0 / प्रव0) राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त(क0नि0) राज्य कर, खटीमा	5 वर्ष
4	श्री विनय कुमार पाण्डेय	उपायुक्त (क0नि0) राज्य कर, विकासनगर	कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	5 वर्ष
5	श्री विनय प्रकाश ओझा	उपायुक्त (क0नि0)–2, राज्य कर, काशीपुर	कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	5 वर्ष
6	श्री संजीव कुमार त्रिपाठी	उपायुक्त (ऑडिट)–2 राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त(क0नि0)–03 राज्य कर, रूड़की	5 वर्ष
7	श्रीमती मनीषा सैनी	उपायुक्त (आई0आर), राज्य कर हरिद्वार	उपायुक्त(ऑडिट)–02 राज्य कर, देहरादून	धारा–17(ख)(चार) के अन्तर्गत अनुरोध ग्राहय योग्य है।

1	2	3	4	5
8	श्री वीर सिंह	उपायुक्त कर निर्धारण, राज्य कर, खटीमा	उपायुक्त(क0नि0)–01 राज्य कर, रूद्रपुर	स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या–03 के अन्तर्गत अनुरोध ग्राह्य योग्य है।
9	श्री तारकेश्वर मिश्रा	उपायुक्त (ऑडिट)–1, राज्य कर, रूड़की	यथावत्	स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या–03 के अन्तर्गत अनुरोध ग्राह्य योग्य है।
10	श्री निखिलेश कुमार श्री वास्तव	उपायुक्त (क0नि0)–4, राज्य कर, देहरादून	यथावत्	5 वर्ष/धारा–17(ख) चार के अन्तर्गत अनुरोध ग्राह्य योग्य है।
11	श्रीमती हेमलता शुक्ला	उपायुक्त (विअनुशा) राज्य कर, हल्द्वानी	कार्यालय–संयुक्त आयुक्त(रिस्क मैने. एण्ड डाटा एना.) राज्य कर, देहरादून	धारा–17(ख) चार के अन्तर्गत अनुरोध ग्राह्य योग्य है।
12	श्रीमती अंजली गुसांई	उपायुक्त (ऑडिट)–2, राज्य कर, रूड़की	कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	धारा–17(ख) के अन्तर्गत अनुरोध ग्राह्य योग्य है।
13	श्री जगदीश सिंह	संयुक्त आयुक्त ग्रेड–2/ उपायुक्त राज्य कर मुख्यालय देहरादून	यथावत्	मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका–304/ 2025 ठा. रणवीर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 24.07.2025 को पारित आदेश के द्वारा सम्प्रति पदोन्नति प्रक्रिया को मा0 न्यायालय द्वारा स्थगित (Stay) किया गया है। इस कारण उक्त पदोन्नति की वर्तमान स्थिति (Status) स्पष्ट न होने के दृष्टिगत मा0 न्यायालय के अगले आदेश तक विभागीय हित में उनके मूल(Substantive) पद (उपायुक्त) का धारक मानते हुए GST Act के अन्तर्गत निर्धारित कार्य करते रहने का निर्णय लिया गया है।
14	श्री नीरज कुमार	संयुक्त आयुक्त ग्रेड–2/ उपायुक्त ऑडिट–2, हरिद्वार सम्बद्ध उपायुक्त(आईआर) राज्य कर हरिद्वार	यथावत्	उपरोक्तानुसार

1	2	3	4	5
15	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला	उपायुक्त (क0नि0)–5, राज्य कर, देहरादून	यथावत्	उपरोक्तानुसार
16	श्री मनीष मिश्रा	कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	यथावत्	उपरोक्तानुसार
17	श्री अभय कुमार पाण्डेय	उपायुक्त (ऑडिट)–2, राज्य कर, काशीपुर	यथावत्	उपरोक्तानुसार
18	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	उपायुक्त (क0नि0)–3, राज्य कर, हरिद्वार	यथावत्	उपरोक्तानुसार
19	श्रीमती मोहिता भण्डारी	उपायुक्त (आन्तरिक पुनरीक्षण), राज्य कर, हल्द्वानी	यथावत्	उपरोक्तानुसार
20	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह	उपायुक्त (क0नि0)–2, राज्य कर, हल्द्वानी	यथावत्	उपरोक्तानुसार

02– उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन/आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

03– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका–304/2025 ठा.रणवीर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 24.07.2025 के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–03

अधिसूचना/विज्ञप्ति

08 जुलाई, 2026 ई0

संख्या 837/XXIV(3)/2026–103717–राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा उल्लास (ULLAS) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित साक्षरता के मानकों को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत, एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,
सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

अधिसूचना

14 जुलाई, 2026 ई0

संख्या 412355/XXIV-C-3/2026–13(28)2019(E-54971)–उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–02 वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–13, वर्ष 2025) के माध्यम से प्रायोजक निकाय राधा स्वामी एजुकेशनल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी, 3/1 बेगमपुर रोहिणी, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित "एथिक्स विश्वविद्यालय" नाम से ग्राम उरेगी, जनपद पौड़ी में एक निजी विश्वविद्यालय निगमित किया गया है।

अतएव, अब राज्यपाल उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम उरेगी जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में "एथिक्स विश्वविद्यालय" नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 412355/XXIV-C-3/2026-13(28)2019 (E- 54971)**, dated July 14, 2026.

NOTIFICATION

July 14, 2026

No. 412942/XXIV-C-3/2026-13(28)2019(E- 54971)--A private University with the name "Ethics University", in Village Uregi, Distt. Pauri Garhwal, Uttarakhand sponsored by the Radha Swami Educational and Vocational Training Society, 3/1 Begumpura Rohini, New Delhi has been incorporated vide the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 (Uttarakhand Act No. 02 of 2024) and Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2025 (Uttarakhand Act No. 13 year 2025).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred under sub-section (1) of section 7 of the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 the Governor is pleased to allow to establish and operate a Private University with the name "Ethics University", in Village Uregi, Distt. Pauri Garhwal, Uttarakhand.

By Order,

Dr. B.V.R.C. PURUSHOTTAM,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/294–भाग 1–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2026 ई0 (श्रावण 17, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 11, 2026

No. 239/XIV-a-41/Admin.A/2016--Shri Puneet Kumar, the then Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 23.03.2026 to 04.04.2026 with permission to prefix 21.03.2026 & 22.03.2026 as Eid & Sunday holiday & suffix 05.04.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 11, 2026

No. 240/XIV/-6/Admin.A/2008--Shri Kuldeep Sharma, 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 16.02.2026 to 28.02.2026 with permission to prefix 15.02.2026 as Sunday holiday and suffix 01.03.2026 to 04.03.2026 as Holi holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

June 15, 2026

No. 241/UHC/Admin.A-2/2026--Pursuant to Rule 27 (ii) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 (as amended); the High Court is pleased to grant the 'Super Time Scale' of ₹ 1,99,100-2,24,100 (J-7) to Shri Sahdev Singh (HJS), w.e.f. 05.07.2024.

NOTIFICATION

June 15, 2026

No. 242/UHC/Admin.A-2/2026--Pursuant to Rule 27 (i) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 (as amended); the High Court is pleased to grant the 'Selection Grade' of ₹ 1,63,030-2,19,090 (J-6) to the following officers of Higher Judicial Service Cadre, for the duration/ from the date mentioned against their names:--

S.No.	Name of the Officer	Present Posting	Date of grant of *'Selection Grade'*
1.	Shri Vijayant Kumar	Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Haldwani, District Nainital	01.11.2019
2.	Shri Shanker Raj	Retired on 28.02.2026	01.01.2020 to 28.02.2026
3.	Shri Gurubaksh Singh	Chairman, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand, Dehradun	01.01.2020
4.	Shri Dharam Singh	District & Sessions Judge, Pauri Garhwal	01.01.2020
5.	Shri Subir Kumar	Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital	01.01.2020
6.	Ms. Neetu Joshi	Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar	01.01.2020
7.	Shri Bindhyachal Singh	District & Sessions Judge, Chamoli	01.01.2020
8.	Shri Manish Mishra	Principal Judge, Family Court, Udham Singh Nagar	01.01.2020
9.	Shri Pankaj Tomar	District & Sessions Judge, Bageshwar	01.01.2020
10.	Shri Sushil Tomar	Principal Judge, Family Court, Nainital	01.01.2020
11.	Shri Rahul Garg	Presiding Officer, Labour Court, Haridwar	01.01.2020
12.	Ms. Neena Aggarwal	District & Sessions Judge, Rudraprayag	01.01.2020
13.	Shri Brijendra Singh	Legal Advisor to Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar	01.01.2020
14.	Shri Kanwar Amninder Singh	1st Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun	01.01.2020
15.	Shri Bharat Bhushan Pandey	Additional Principal Judge-I, Family Court, Roorkee, District Haridwar	01.01.2020
16.	Shri Arvind Kumar	Additional Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand, Dehradun	01.01.2020

17.	Shri Sayan Singh	Secretary-cum-Registrar, State Level Police Complaint Authority, Dehradun	01.01.2020
18.	Ms. Monika Mittal	1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun	01.01.2020
19.	Ms. Neelam Ratra	1st Additional District & Sessions Judge, Haridwar	01.01.2020
20.	Shri Manoj Garbyal	1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar	01.01.2020
21.	Shri Vinod Kumar	Additional Principal Judge, Family Court, Vikasnagar, District Dehradun	01.01.2020
22.	Ms. Anjushree Juyal	Judge, Family Court, Almora	01.01.2020
23.	Ms. Pritu Sharma	Additional District Judge, Commercial Court, Dehradun	01.01.2020
24.	Shri Sujeet Kumar	1st Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital	16.04.2020
25.	Shri Mohammad Sultan	Retired on 31.05.2026	16.04.2020 to 31.05.2026
26.	Shri Mahesh Chandra Kaushiwa	2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun	16.04.2020
27.	Ms. Shadab Bano	Additional Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital	16.04.2020
28.	Shri Nasim Ahmad	Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal	16.04.2020
29.	Ms. Archana Sagar	Additional Principal Judge-II, Family Court, Roorkee, District Haridwar	08.08.2021
30.	Shri Om Kumar	Additional Principal Judge, Family Court, Rishikesh, District Dehradun	07.08.2021
31.	Shri Sanjeev Kumar	1st Additional District & Sessions Judge, Nainital	24.02.2023
32.	Shri Ambika Pant	1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar	05.07.2024
33.	Ms. Vijay Lakshmi Vihan	Presenting Officer, National Human Rights Commission, New Delhi	05.07.2024
34.	Shri Pradeep Kumar Mani	Member-Secretary, Uttarakhand SLSA, Nainital	29.01.2026
35.	Shri Anirudh Bhatt	Additional District Judge, Commercial Court, Haldwani, District Nainital	29.01.2026

By Order of the Court,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

July 28, 2026

No. F-9(37)/RG/UERC/2026/655 : In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Sections 61, 66, and 86 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely –

Chapter 1
Preliminary

1. Short Title, Extent, and Commencement

1.1. These Regulations shall be called the **"Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2026".**

1.2. These Regulations shall extend to the whole of Uttarakhand.

1.3. These Regulations shall come into force from the date of notification in the official gazette.

2. Objective

2.1. The objective of these Regulations is to enable the implementation of Resource Adequacy framework by outlining a mechanism for planning of generation resources for reliably meeting the projected demand in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix.

2.2. The Resource Adequacy framework shall cover a mechanism for demand assessment and forecasting, generation resource planning, procurement planning, its monitoring and compliance.

3. Scope and Applicability

3.1. These Regulations shall apply to the Generating Companies, Distribution Licensee(s), State Load Despatch Centre, State Transmission Utility, Transmission Licensee(s) and other grid connected entities within the State of Uttarakhand.

4. Definitions

4.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires,

a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and subsequent amendments thereof;

b) "**Authority**" or "**CEA**" means Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;

c) "**Capacity**" means the installed nameplate capacity of the resource.

d) "**Capacity Credit**" or "**CC**" means the firm capacity for meeting Resource Adequacy Requirements, expressed as a percentage of an installed nameplate capacity;

e) "**CERC**" means the Central Electricity Regulatory Commission;

f) "**Commission**" or "**State Commission**" means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) constituted under the Act.

g) "**Electric Power Survey**" or "**EPS**" means a periodic electric power survey conducted by the Central Electricity Authority to assess the electricity demand on medium and long-term basis for each DISCOM/State/Union Territory/Region and for the Country;

h) "**Expected Energy Not Served**" or "**EENS**" means the expected amount of energy (MUs) that may not be served for each year within the time horizon period for Resource Adequacy planning;

i) "**Load Factor**" is calculated by dividing total electrical energy requirement for a given period of time by the product of maximum demand and that specific period of time. The formulae for calculating load factor on monthly and yearly basis are:

Monthly Load Factor (in %)

= (Energy Requirement in MU * 1000) * 100 / (Peak Demand in MW * No. of days in the Month * No. of hours in a day)

Yearly Load Factor (in %)

= (Energy Requirement in MU * 1000) * 100 / (Peak Demand in MW * No. of days in the year * No. of hours in a day)

j) "**Load Diversity Factor**" means the ratio of the sum of individual non-coincident maximum loads of Electricity Distribution Divisions of the Distribution Licensee(s) to the

Maximum Demand of the Distribution Licensee(s)operational area.

$$Load\_Diversity\_Factor$$

$$=\Sigma(Individual\ non\_coincident\ maximum\ loads\ of\ \text{Electricity Distribution Divisions}) / (Maximum\ Demand\ of\ the\ \text{Distribution Licensee(s)}\ Operational\ area)$$

Load Diversity Factor is always greater than 1.

k) "**Load Research**" means the systematic process of collecting and analyzing electricity consumption data from customers, to understand when and how the energy is used, which would enable the utilities to predict future demand and manage infrastructure like transformers, ultimately supporting cost-effective demand-side management (DSM).

l) "**Long-Term**" means duration exceeding five years for development of demand forecasting and generation resource planning;

m) "**Long-Term Distribution Resource Adequacy Plan**" or "**LT-DRAP**" means plan for assessment of long-term resource adequacy by the Distribution Licensee(s);

n) "**Long-Term Power Procurement**" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding five years;

o) "**Loss of Load Probability**" or "**LOLP**" means probability that a system's load may exceed the generation and firm power contracts available to meet that load in a year;

p) "**Medium-Term**" means duration exceeding one year and up to five years for development of demand forecasting and generation resource planning;

q) "**Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan**" or "**MT-DRAP**" means plan for assessment of medium-term resource adequacy by the Distribution Licensee(s);

r) "**Medium-Term Power Procurement**" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding one year and up to five years;

s) "**Month**" means a calendar month as per the Gregorian Calendar;

t) "**Net Load**" means the load derived upon exclusion of actual renewable energy generation (MW) from gross load prevalent on the grid during any time-block;

u) "**Normalized Energy Not Served**" or "**NENS**" is the total expected load shed due to supply shortage (MWh) as a percentage (%) of the total system energy, and, therefore,

represents an overall percentage of system load that cannot be served.

v) **'OTC Platform'** means an Over-The-Counter Platform operating in terms of Power Market Regulations issued by the Central Electricity Regulatory Commission.

w) **"Planning Reserve Margin"** or **"PRM"** means a percentage of the capacity over and above the State's coincident share in national peak demand, as may be laid down by Authority and approved by the Commission from time to time for the purpose of generation resource planning;

x) **"Power Exchange"** means any Exchange operating as Power Exchange for electricity in terms of the Regulations issued by the Central Electricity Regulatory Commission;

y) **"Power Purchase Agreement (PPA)"** means the agreement entered into between the Procurer(s) and the Seller pursuant to which the Seller shall supply power to the Procurer(s) as per the terms and conditions specified therein and approved by the Commission;

z) **"Power Sale Agreement (PSA)"** shall mean the back-to-back agreement entered into between the Buying Entity(s) and the Intermediary Procurer/trader for onward sale of power purchased under any PPA;

aa) **"Power Supply Agreement"** shall mean the agreement entered into between the Procurer(s) and the Seller pursuant to which the Seller shall supply power to the Procurer(s) as per the Ministry of Power Guidelines for long-term Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own and Operate (DBFOO) basis and sourcing fuel as provided under Model Bidding Documents including allocation of coal under B(I), B(III) and B(IV) of SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) Policy;

bb) **"Resource Adequacy"** or **"RA"** means a mechanism to ensure adequate generation resources to serve expected demand (including peak, off peak and in all operating conditions) reliably in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix and with a focus on integration of environmentally benign technologies after taking into account the need, inter alia, for flexible resources, storage systems for energy shift, and demand response measures for managing the intermittency and variability of renewable energy sources;

cc) **"Short-Term"** means duration up to one year for development of demand forecasting and generation resource planning;

dd) "Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan" or "ST-DRAP" means plan for assessment of short-term resource adequacy by the Distribution Licensee(s);

ee) "Short-Term Power Procurement" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration of up to one year;

ff) "SLDC" means the State Load Despatch Centre of Uttarakhand

gg) "State" means the State of Uttarakhand;

hh) "Year" means financial year commencing on 1st April of the year and ending on 31st March of the succeeding year.

4.2. The words and expressions used in these Regulations, not specifically defined herein above, but defined in the Act or other Regulations of the Commission or CEA Guidelines, shall have the same meaning as assigned to them in the Act, Regulations or CEA Guidelines.

Chapter 2

General

5. Resource Adequacy Framework

5.1. Resource Adequacy framework shall comprise planning of generation resources for reliably meeting the projected demand in compliance with specified reliability standards for serving the load with an optimum generation mix and shall cover following steps:

a) Demand assessment and forecasting;

b) Generation resource planning;

c) Procurement planning;

d) Monitoring and compliance.

5.2. The Resource Adequacy shall be developed and prepared for a planning period of 10 (ten) years on annual rolling basis.

5.3. The long, medium and short term for the purpose of these Regulations shall be considered as:

a) Long-term procurement plan for a period exceeding five years and up to ten years; and

b) Medium-term procurement plan for a period exceeding one year and up to five years; and

c) Short-term procurement plan for a period up to one year.

5.4. The Distribution Licensee(s) shall develop and prepare Long-Term Distribution Resource Adequacy Plan (LT-DRAP), Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan (MT-DRAP), and Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan (ST-DRAP) in accordance with the conditions outlined under these Regulations.

Chapter 3
Demand Assessment and Forecasting

6. Long-Term and Medium-Term Demand Forecast

6.1. The Distribution Licensee(s) shall develop and prepare demand assessment and forecasting at State periphery in accordance with the guidelines for Long-term and Medium-term power demand forecast issued by Central Electricity Authority (CEA) from time to time.

6.2. Demand assessment and forecasting shall cover hourly or sub-hourly assessment and forecasting of demand within the distribution area of Distribution Licensee(s) for multiple horizons, viz (Long-term/Medium-term/Short-term) shall be done using comprehensive input data, policies, drivers and scientific mathematical modelling tools.

6.3. The SLDC shall be responsible for providing Deviation Settlement Mechanism (DSM) accounts to the Distribution Licensee(s) of previous financial year latest by 21st April of each year, and the Distribution Licensee(s) shall utilize the same for preparing its forecasts.

6.4. The Distribution Licensee(s) shall be responsible for the assessment and forecasting of demand (MW) and energy requirement (MUs).

6.5. The Distribution Licensee(s) shall prepare the load and energy forecast for each consumer category as specified by the Commission in its Retail Supply Tariff Order from time to time.

6.6. The Distribution Licensee(s) shall determine the load forecast for a consumer category by adopting any of the following and/or combination of following methodologies:

a) Trend Analysis, i.e. Year on Year /compounded annual growth rate (CAGR) for past period and time series analysis;

b) End Use or Partial End Use method;

c) Auto-regressive integrated moving average (ARIMA) method;

d) Artificial Intelligence (AI) including machine learning, Artificial Neural Network (ANN) techniques; and

e) Econometric Modelling (specifying the parameters used, algorithm, and source of data).

6.7. The Distribution Licensee(s) may use Electric Power Survey (EPS) projections as base and/or any methodology other than the above-mentioned methodologies after providing detailed justification for the methodology adopted for demand forecasting. The Distribution Licensee(s) shall use the best fit of various methodologies for the purpose of demand/load forecast after taking into consideration various scenarios such as optimistic, business as usual, and pessimistic, as specified under Regulation 6.16 of these Regulations.

6.8. For the purpose of methodology to be used for energy forecasting of a consumer category, the Distribution Licensee(s) shall conduct statistical analysis and select the method for which the standard deviation is lowest, and R-squared (coefficient of determination) is highest.

6.9. The Distribution Licensee(s) shall utilize state-of-the-art tools, scientific and mathematical methodologies, and comprehensive database such as, but not limited to, weather data, historical data, demographic and econometric data, consumption profiles, impact of policies and drivers, etc. as may be applicable to the Distribution Licensee(s) control area.

6.10. The Distribution Licensee(s) may modify the energy forecast obtained on either side, for each consumer category, by considering the impact of the following activities. The impact shall be considered by developing trajectories for each activities based on the economic parameters, policies, historical data, and projections for the future:-

a) Demand-Side Management;

b) Open Access;

c) Distributed Energy Resources;

d) Deviation Settlement Mechanism and demand response measures;

e) Electric Vehicles and EV Charging Stations;

f) Tariff Signals including Time of the Day (ToD) Tariff;

g) Changes in specific energy consumption;

h) Increase in commercial activities with electrification;

i) Increase in number of agricultural pump sets and its solarization;

j) Changes in consumption pattern of seasonal consumers;

k) Availability of supply;

l) Impact of important festivals, working days or non-working days, Peak and Off-Peak hours load pattern; and

m) Energy Storage System (ESS), e.g. Battery ESS, Pumped Storage System etc.; and

n) Policy influences such as 24x7 supply to all consumers, LED penetration, efficient use of agriculture pumps, fans/ACs/ appliances, increased use of appliances for cooking/ heating/cooling applications, electrification policies, distributive energy resources, storage, policies which can impact econometric parameters, impact of national hydrogen mission, energy efficiency measures, energy saving and conservation interventions, etc. For each policy, a separate trajectory should be developed for each consumer category.

6.11. The Distribution Licensee(s) may take into consideration any other factor not mentioned in Regulation 6.10 of these Regulations after providing detailed justification for its consideration.

6.12. The Distribution Licensee(s) shall annually conduct Load Research for consumer categories and the long and medium-term load profiles of the consumer categories for which load research has been conducted may be refined on the basis of load research analysis using smart meter infrastructure. The load research shall include monitoring, collecting, and analyzing electrical usage, including consumption patterns, socio-economic factors, and peak load timing. This data is essential for long/medium term and short-term forecasting to avoid capacity shortages. A detailed explanation for refinement conducted must be properly documented by the Distribution Licensee(s).

6.13. The summation of energy forecast (MUs) for various consumer categories after adjusting energy forecast of captive consumers, prosumers and open access consumers as per Regulations 6.6 to 6.12 of these Regulations, as the case may be, shall form the basis of energy forecast (MW) for the Distribution Licensee(s) at consumer level.

6.14. The Distribution Licensee(s) shall calculate the energy forecast (MUs) of the State by considering distribution losses and Intra/Inter-State transmission loss trajectory approved by the Commission, and in case where no trajectory is approved for future years, as per realistic loss trajectory proposed by the Licensee(s) :

Provided that for the purposes of estimating Aggregate Revenue Requirement (ARR) for ensuing years and approval of true-up of previous years, Distribution/Aggregate Technical

and Commercial (AT&C) Losses trajectory as specified by the Commission from time to time shall be considered.

6.15. The peak demand (in MW) shall be determined by considering the average load factor, load diversity factor, seasonal variation factors for the last three years, and the energy forecasts (in MUs) obtained in accordance with Regulation 6.14 of these Regulations. If any other appropriate load factor is considered for future years, a detailed justification shall be provided by the Distribution Licensee(s) for its consideration.

6.16. The Distribution Licensee(s) shall conduct sensitivity and probability analysis to determine the optimistic demand forecast. It shall also develop long-term and medium-term demand forecasts for possible scenarios, while ensuring that at least three different scenarios (optimistic, business as usual, and pessimistic scenarios) are developed.

6.17. The Distribution Licensee(s) shall maintain the database of actual energy consumption in its area of operation, block-wise/hourly/monthly for all consumer categories, which shall form the basis for future demand forecasting for intervals/periods as notified by the Commission from time to time.

7. Short-Term Demand Forecast

7.1. The Distribution Licensee(s) shall develop a methodology for hourly or sub-hourly demand forecasting at State periphery and shall maintain a historical database.

7.2. For the purpose of ascertaining hourly load profile and for assessment of contribution of various consumer categories to peak demand, load research analysis shall be conducted, and influence of demand response, load shift measures, time of use shall be factored in by the Distribution Licensee(s) taking into consideration the inputs from State Load Despatch Centre (SLDC), based on the relevant data available. A detailed explanation for methodology adopted must be properly documented by the Distribution Licensee(s).

7.3. The Distribution Licensee(s) shall utilize state-of-the-art tools, scientific and mathematical methodologies (including, inter alia, the methodologies as listed in Regulation 6.6 of these Regulations, as deemed relevant), and comprehensive data but not limited to weather data, historical data, demographic and econometric data, consumption profiles, policies and drivers, etc. as may be applicable to the area of Distribution Licensee(s).

8. Aggregation of Demand Forecast

8.1. The Distribution Licensee(s) shall estimate and prepare hourly or sub-hourly 1-year Short-term

(ST), 5-year Medium-term (MT) and 10-year Long-term (LT) demand forecasts at State Periphery on a rolling basis and submit the same to SLDC by 30th April of each year for the ensuing year(s).

8.2. SLDC shall aggregate the respective demand forecasted by the Distribution Licensee(s), duly considering the diversity of the State, congruency, seasonal variation aspects and shall prepare the monthly 1-year Short-Term (ST), 5-year Medium-Term (MT) and 10-years Long-Term (LT) forecasts for the entire State after considering the Intra state transmission loss as approved by the Commission in the Business Plan of the STU from time to time and the transmission loss figure available for the last year of the Business plan shall be considered for assessment of demand for the future years.

8.3. SLDC shall submit the state-level aggregate demand forecasts (MW and MUs) for Long-Term, Medium-Term and Short-Term to the Authority, NLDC, NRLDC, STU by 31st May of each year for the ensuing year(s).

Chapter 4

Generation Resource Planning

9. Preparation of Generation Resource Planning

9.1. Distribution Licensee(s) shall plan and assess the required generation resources considering the existing resources, upcoming resources (not yet commissioned), capacity credit and incremental capacity requirement to meet forecasted demand including planning reserve margin (PRM).

9.2. Generation Resource Planning shall involve the following steps namely,

a) Capacity crediting of generation resources;

b) Assessment of planning reserve margin; and

c) Ascertaining resource adequacy requirement and allocation to Distribution Licensee(s).

9.3. The Distribution Licensee(s) shall map all its existing resources, upcoming resources, and retiring resources to develop the resource map in MW for the Long-term and Medium-term power procurement plan.

9.4. The mapping shall include critical characteristics and parameters of the generating machines, such as heat rate, auxiliary consumption, ramp-up rate, ramp-down rate, etc., for thermal

machines; hydrology and machine characteristics etc. for hydro machines; and renewable resources, their Capacity factors/CUFs, etc. for renewable resource-based power plants to be considered in the resource plan. All the characteristics and parameters for each generating machine considered shall be provided in the resource plan. Some of the important parameters that would be considered for this resource characteristic assessment shall include but not limited to following:

a) Planning Reserve Margin;

b) Actual demand met by the State/Distribution Licensee(s) in hourly time block resolutions for last 5 years;

c) Estimated load growth during the planning period;

d) Critical characteristics, machine characteristics, hydrology for hydro machines and technical parameters of thermal and hydro generation plants, such as:

   i. Name of plant, location (State/Region);

   ii. Capacity (MW) (for existing and planned capacities);

   iii. Heat Rate for thermal generating stations;

   iv. Auxiliary Consumption (MW);

   v. Maximum and Minimum Generation Limits (MW);

   vi. Ramp Up and Ramp Down Rate (MW/min);

   vii. Start-up time (Minimum up and down time);

   viii. Plant Availability Factor (% of time), etc.; and

   ix. Capacity utilization factor (CUF) for renewable resource-based power plants.

e) All the characteristics and parameters with their values for each generating plant considered shall be provided in the resource plan;

f) Under-construction capacity/retirement of generation capacity/ contracted capacity/ bilateral contracts/renovation;

g) Potential technologies, gestation periods and lifetime of different assets;

h) Capacities and generation profile of renewable generation;

i) Historical forced outage rates and planned maintenance rates of generation capacities;

j) Renewable Purchase Obligation (RPO) including Energy Storage Obligation targets, etc.;

k) Constraints such as penalties for unmet demand, forced outages, and system emission limits as defined in State Grid Code and Indian Electricity Grid Code and emission norms specified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) shall be identified and enlisted.

l) Transmission expansion plans with timelines

m) Evacuation arrangements with timelines for RE generation resources.

9.5. The Distribution Licensee(s) shall also include a Planning Reserve Margin (PRM) as specified by the Authority or the Commission, as the case may be. In the absence of any guidelines from the Commission, the Distribution Licensee(s) can consider suitable planning reserve with proper justification, which will be subject to approval by the Commission. The value of planning reserve margin considered shall be stipulated in the resource plan along with justifications.

10. Capacity Crediting of Generation Resources

10.1. The Distribution Licensee(s) shall compute Capacity Credit (CC) factors for their contracted generation resources by applying the net load-based approach as outlined hereunder. The average of the Capacity Credit (CC) factor for each type of contracted generation resource for the preceding five years on a rolling basis shall be considered as Capacity Credit factor for the purpose of Generation Resource Planning.

10.2. The Net Load based approach/methodology for the determination of Capacity Credit (CC) factors for generation resources shall be adopted as under.

The following clause (a) to (f) outlines CC factor calculation for Solar generation source as an illustration which shall be applied for calculation of CC factor for other generation sources also:

a) For each year, the hourly recorded Gross Load, i.e. total demand at State Periphery (in MW) for 8760 hours (8784 hours for leap year) (or sub-hourly time-blocks) shall be arranged in descending order;

b) For each hour, the Net Load (in MW) shall be calculated by subtracting the Actual solar generation capacity (in MW) corresponding to that Gross load for 8760 hours (8784 hours for leap year) (or sub-hourly time-blocks) and then arranged in descending order;

c) The difference between these two load duration curves mentioned under clause (a) and

(b) above represents the contribution of capacity factor of solar generation;

d) Installed capacity (in MW) of solar generation capacity shall be summed up corresponding to the top 250 load hours (or sub-hourly time-blocks) as computed in clause (b) above. The selection for 250 top load hours (or sub-hourly time-blocks) shall be considered from the arranged descending order of Net Load hours;

e) Resultant CC factor shall be as per formula below:

$$\text{CC factor} = \frac{\text{Sum of Solar Generation (MW) for top 250 load hours}}{\text{Sum of Installed Solar Capacity (MW) for top 250 load hours}}$$

f) The process for CC factor determination shall be undertaken for each year for duration of past five-years and the resultant CC shall be the average of CC values of past 5 years:

Provided that at the time of determining CC factor considering past five-years duration values, the Distribution Licensee(s) shall exclude abnormal values during the year for following events or circumstances, but not limited to:-

i. Act of God including but not limited to lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, natural disaster or exceptionally adverse weather conditions, which are in excess of the statistical measures for the last hundred years; or

ii. Any disaster declared by the Central Government under Disaster Management Act as amended from time to time; or

iii. Any act of war, invasion, armed conflict or act of a foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist, or military action.

10.3. CC factors for hydro generation resources shall be computed based on water availability with different CC factors for run-of-the-river hydro power projects and dam-based/storage-based hydro power projects.

10.4. CC factor for thermal resources shall be computed based on fuel availability and planned/ forced outages.

10.5. For the purpose of generation resources, contribution of CC factor for such generation resource where such resource is located in the grid (namely inter-state or intra-state generation resource whose entire capacity is not tied up with the Distribution Licensee(s), as the case may be) as

contracted by the Distribution Licensee(s) shall be considered. For this purpose, CC factors as specified by Authority or as approved by the Commission shall be considered.

10.6. The Distribution Licensee(s) shall share CC factors for their contracted resources alongwith justification for its computations with SLDC by 15th May of each year for the ensuing year(s).

10.7. SLDC shall calculate state-specific CC factors considering the aggregate State Demand and State Net Load and contracted RE generation resources available in the State and shall submit such CC factor information to the Authority, NLDC and NRLDC by 31st May of each year for ensuing year(s).

11. Assessment of Planning Reserve Margin (PRM)

11.1. Planning Reserve Margin (PRM) as a percentage of peak load represents the excess generation resource or planning reserve required to be considered for the purpose of generation resource planning.

11.2. Planning Reserve Margin (PRM) factor shall be based on the reliability indices in terms of Loss of Load Probability (LOLP) and Normalized Energy Not Served (NENS) as may be specified by the Authority or separately computed by the Distribution Licensee(s) and STU/SLDC at State level, subject to approval by the Commission, and the same shall be considered by the Distribution Licensee(s) in their planning for resource adequacy requirement and generation resource capacity planning.

11.3. The Distribution Licensee(s) may consider higher planning reserve margins, subject to prior approval from the Commission.

11.4. The capacity planning by the Distribution Licensee(s) and the State level resource adequacy planning by STU/ SLDC shall factor in PRM while developing the state-level Integrated Resource Plan.

12. Resource Adequacy Requirement and its Allocation

12.1. The Distribution Licensee(s) shall determine capacity requirement to meet demand and PRM considering available capacity adjusted for capacity crediting for existing and planned contracted generation resources.

12.2. The available capacity as determined in Regulation 12.1 shall then be plotted over a time axis of 15-minute intervals or longer, but not more than one hour. This shall form the resource map of the Distribution Licensee(s).

12.3. The Distribution Licensee(s) shall subtract the resource map developed in Regulation 12.2 from the demand forecast developed in Regulation 6 of these Regulations to identify the resource gap. The resource gap in terms of RA compliance for the Distribution Licensee(s) for the long term and medium term shall be developed in the manner as specified in these Regulations.

12.4. The Distribution Licensee(s) shall conduct sensitivity and probability analysis to determine the optimistic resource gap. It shall also develop Long-term, Medium-term, and Short-term resource gap plans for possible demand forecasting scenarios, while ensuring at least three different scenarios (optimistic, business as usual, and pessimistic Scenario) are developed. Based on optimistic scenario, the Distribution Licensee(s) shall undertake development of Long-term, Medium-term, and Short-term Distribution Resource Adequacy Plan exercise to meet the Resource Adequacy target requirement.

12.5. The Distribution Licensee(s) shall submit the RA plans (LT-DRAP, MT-DRAP & ST-DRAP) so developed to the Commission by 31st August of each year. The Distribution Licensee(s) shall also submit the RA Plans to the STU and SLDC for further examination so as to apprise the Commission as per these Regulations.

12.6. **Long-Term Distribution Resource Adequacy Plan (LT-DRAP)**

a) RA requirement planning shall be done with reference to national coincident peak to optimize the requirement of incremental capacity addition through an annual rolling plan. Long-term National Resource Adequacy Plan (LT-NRAP) as may be published by Central Electricity Authority to determine the optimal Planning Reserve Margin (PRM) requirement at the national level for ensuring reliable supply targets and Short-term National Resource Adequacy Plan (ST-NRAP) as may be published by NLDC for a one-year look-ahead shall act as guidance for the Distribution Licensee(s) for undertaking the Resource Adequacy exercises.

b) Based on the allocated share in national peak provided in LT-NRAP for the State, the Distribution Licensee(s) shall ascertain its share in the national peak within 15 days of the publication of LT-NRAP.

c) The Distribution Licensee(s), based on the share in national peak provided in LT-NRAP, shall plan to contract the capacities over and above the State coincident demand in national peak prescribed by LT-NRAP or procure higher to meet their Resource Adequacy Requirement (RAR) at the time of national peak.

d) The Distribution Licensee(s) shall demonstrate to the Commission 100% tie-up for the first year and a minimum 90% tie-up for the second year to meet the requirement of their contribution towards meeting national peak. Only resources with long / medium / short-term contracts shall be considered to contribute to the RAR.

e) For subsequent three years, the Distribution Licensee(s) shall furnish a plan to meet estimated requirement of their contribution to meet national peak for the Commission's approval.

f) The Distribution Licensee(s) shall submit the details of the contracted capacities for the ensuing years for meeting RAR of the national peak to SLDC within 15 days from the date of approval from the Commission. SLDC shall aggregate the total contracted capacities at the state level and submit the information to NLDC/NRLDC, under intimation to the Commission, within 15 days from the date of receipt from the Distribution Licensee(s).

g) The Distribution Licensee(s) shall keep the share of Long-term contracts in the range of 75-80% of the RAR and Medium–term contracts in the range of 10% - 20% of the RAR, while the balance of RAR shall be met through Short-term contracts:

Provided that power procurement through exchange, shall not be considered towards the contribution for meeting RAR.

h) The contract mix mentioned under Regulation 12.6(g) of these Regulations may be periodically reviewed by the Commission.

i) The LT-DRAP shall be carried out by the Distribution Licensee(s) on an annual rolling basis considering the contracted capacity as a part of the system, which shall be optimized for additional capacity required.

j) The Distribution Licensee(s) through LT-DRAP, shall demonstrate to the Commission their plan to meet their Peak demand and energy requirement with a mix of Long-term, Medium-term, and Short-term contracts.

k) The share of long-term contracts in the entire mix of the contracts of the Distribution Licensee(s) shall be at least equal to the maximum of the quantum of long-term contracts determined for meeting RAR of national peak as per Regulation 12.6 (c) of these Regulations, and quantum obtained from LT-DRAP for fulfilling own energy and peak requirement as per Regulation 12.6(l) of these Regulations.

l) The Distribution Licensee(s) shall prepare a 10-year Long-term Distribution Resource Adequacy Plan (LT-DRAP) to meet the peak demand and energy requirement for the State of Uttarakhand including State's contribution to meet national peak (PRM).

m) The Distribution Licensee(s) while formulating the LT-DRAP shall also consider the constraints mentioned in **Annexure–I** of these Regulations.

n) The Distribution Licensee(s) may take inputs from the LT-NRAP like PRM, capacity credits, etc. while formulating the LT-DRAP and shall submit their plans to CEA by 30th September of each year for the ensuing year(s) for validation.

o) The Distribution Licensee(s) shall submit the LT-DRAP duly vetted by CEA along with necessary supporting documents, formats (enclosed as **Annexure-II** to these Regulations) and details for meeting RAR, to the Commission for approval within 15 days from the date of receipt of CEA's approval.

12.7. **Medium-Term Distribution Resource Adequacy Plan (MT-DRAP)**

a) The Distribution Licensee(s) shall prepare a 05-year MT-DRAP in line with the approach and methodology as discussed in Regulation 12.6 above.

b) The Distribution Licensee(s) shall submit the MT-DRAP to the Authority and the NLDC by 31st August of each year for the ensuing year(s).

c) The Distribution Licensee(s) shall submit the MT-DRAP duly vetted by CEA along with necessary supporting documents, formats (enclosed as **Annexure-II** to these Regulations) and details for meeting RAR, to the Commission for approval alongwith LT-DRAP.

12.8. **Short-Term Distribution Resource Adequacy Plan (ST-DRAP)**

a) SLDC shall prepare one-year look ahead ST-DRAP (Short-term Distribution Resource Adequacy Plan) on an annual basis for operational planning, at the State level based on the LT-DRAP study results. The SLDC shall review the ST-DRAP on a daily, weekly, monthly and quarterly basis based on actual availability of generation resources.

b) The Distribution Licensee(s) shall submit the ST-DRAP to the Authority and the NLDC by 31st August of each year for the ensuing year(s).

c) The Distribution Licensee(s) shall submit the ST-DRAP duly vetted by CEA along with necessary supporting documents, formats (enclosed as **Annexure-II** to these Regulations) and details for meeting RAR, to the Commission for approval alongwith LT-DRAP.

12.9. The Commission shall approve Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) of the Distribution Licensee(s) within 120 days of submission by the Distribution Licensee(s) of the duly vetted Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) by CEA for the ensuing year(s) including annual rolling plans, as the case may be, upon taking into consideration various scenarios as well as allocation of Resource Adequacy requirement allocated to the State/Distribution Licensee(s) based on its contribution to the National/state peak respectively as determined by Authority/NLDC/RLDC and STU/SLDC, as the case may be.

Chapter 5

Procurement Planning

13. Procurement planning shall consist of:

a) Determining the optimal power procurement resource mix;

b) Deciding on the modalities of procurement type and tenure; and

c) Engaging in the capacity trading or sharing of capacity to minimize risk of resource shortfall and to maximize rewards of avoiding stranded capacity or contracted generation.

14. Procurement Resource Mix

14.1. In power procurement strategy, the Distribution Licensee(s) shall ensure an optimal procurement generation resource mix and also facilitate smooth integration of Renewable Energy (RE) sources in its portfolio of power procurement resource options, while meeting reliability standards and Renewable Purchase Obligation targets. Further, the future capacity mix may comprise of existing capacities, planned capacities and capacity addition required to meet the increasing demand of the Distribution Licensee(s) considering appropriate gestation period of the generation resource.

14.2. For identification of the optimal generation procurement resource mix, optimization techniques and least-cost modelling shall be employed by the Distribution Licensee(s) in order to avoid stranded capacity. The Distribution Licensee(s) shall engage in adoption of least cost modelling and optimization techniques and shall demonstrate the same in its overall power procurement planning exercise to be submitted to Commission for approval by 30th April of each Financial Year.

14.3. The Distribution Licensee(s) shall contract the optimal portfolio of resources to meet

Distribution Licensees' future demand and Resource Adequacy Requirement (RAR) obligations, based on the output derived from the LT-NRAP study results.

14.4. The Distribution Licensee(s) shall consider Long / Medium / Short-term contracts of generation resources towards the contribution for meeting RAR:

Provided that power procurement through power exchanges, shall not be considered towards the contribution for meeting RAR.

14.5. The Distribution Licensee(s) shall contract additional resources based on the LT-DRAP to meet its own peak demand.

14.6. The power capacity procurement from Renewable Energy sources for fulfilling the RPO targets shall be carried out as per Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2023, as amended from time to time.

14.7. The power procurement from Wind, Solar PV, Wind Solar Hybrid, and Round the Clock (RTC) generation sources shall be carried out as per the guidelines for tariff based competitive bidding process notified by the Ministry of Power.

14.8. The Distribution Licensee(s) shall contract storage capacity corresponding to the results of LT- DRAP capacity addition requirement for future years from Battery Energy Storage System (BESS) or Pumped Storage Projects (PSP) or any other storage technology as per the guidelines for tariff based competitive bidding process notified by the Ministry of Power.

14.9. The Distribution Licensee(s) may contract power through State Generating Stations/ Central Generating Stations/ Independent Power Producers (IPPs)/ Captive Power Plants (CPPs)/ Renewable Power Plants including Co-Generation Plants/Central Agencies /State Agencies/ Intermediaries / Traders / Aggregators / Power Exchanges or through Bilateral Agreements / Banking Arrangements with other Distribution Licensee(s) and any other sources as may be approved by the Commission.

15. Procurement Type and Tenure

15.1. The Distribution Licensee(s), while determining the modalities and tenure of procurement of resources, shall ensure that procurement contracts shall be decided first within the region, subject to the least cost resource availability considering transmission constraints and cost of transmission for procurement from outside the region and then across regions if necessary.

15.2. The Distribution Licensee(s) shall identify the generation resource mix and also procurement strategy in Long-term, Medium-term and Short-term period and seek approval of the Commission.

15.3. The Distribution Licensee(s) in its overall power procurement planning approach shall employ greater emphasis on adequate contracting through Long-Term and Medium-Term arrangements. However, the Distribution Licensee(s) shall ensure that entering into new Long-Term and Medium-Term contracts does not contribute towards accumulation of stranded capacity and additional burden to the consumers on account of fixed cost associated with stranded capacity.

15.4. The Distribution Licensee(s) through annual rolling plan shall ensure incremental capacity addition through Long-term/Medium-term/Short-term duly factoring the existing and planned procurement arrangements of the Distribution Licensee(s).

15.5. The Distribution Licensee(s) shall submit the state-level aggregated Annual Rolling Plan to NRLDC by 20th January of each year for the ensuing year(s).

15.6. The Distribution Licensee(s) must ensure that procurement process for the projected demand is undertaken and completed sufficiently in advance so that the procured capacity becomes available when it is required to serve the projected load. The following table gives the number of years before which procurement process must be completed in advance as compared to the year of projected requirement for various types of generation and types of procurement:

Resource	Long Term	Medium Term
Coal/Lignite	7	2
Hydro	9	2
Solar	2	1
Wind	3	1
PSP	5	3
Other Storage (including BESS)	2	1
Nuclear	9	3

16. Approval of Power Purchase Agreement

16.1. All procurement of Long/ Medium/ Short-Term power from various sources shall be carried out as per the Guidelines/ Rules/ Regulations/ Policies issued by the Commission/ Central Government from time to time.

16.2. Any new capacity/ power purchase agreement for Long/Medium-term or amendments to existing Long/Medium-Term Power Purchase Agreement (PPA)/ Power Sale Agreement

(PSA) entered into by the Distribution Licensee(s) shall be subject to the prior approval of the Commission. The Petition seeking approval shall demonstrate the following:

i. Necessity;

ii. Reasonability of cost;

iii. Promoting efficiency, economy, equitability and competition;

iv. Conformity with requirements of quality, continuity and reliability of supply;

v. Conformity with safety and environmental standards;

vi. Conformity with criterion of power purchase as laid down by the Commission;

vii. Conformity with policy directives of the State Government and policies issued by the Government of India viz. National Electricity Policy, Tariff Policy, Long-Term and Short-Term power procurement guidelines etc.

16.3. The Distribution Licensee(s) shall submit the list of all existing Power Purchase Agreements executed with different conventional power plants as well as RE Generators along with the Resource Adequacy plan.

17. Sharing of Capacity

17.1. The Distribution Licensee(s) shall duly factor in the possibility of Long-term / Medium-term/ Short-term capacity sharing while preparing the Resource Adequacy plan and optimally utilize the platform for Inter-State capacity sharing or trading mechanism created by the Central Commission/Central Government to optimize the capacity costs as far as possible.

17.2. The Distribution Licensee(s) shall submit information about contracted capacity to the SLDC and STU for compliance verification.

18. Variation in Power Purchase

a) The Distribution Licensee(s) may undertake additional power procurement during the year with prior approval of the Commission , over and above the approved resource adequacy procurement plan, where there has been an increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the year due to unforeseen circumstances or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources.

b) The Distribution Licensee(s) may enter into a Short-term arrangement or agreement for procurement of power when faced with emergency conditions that threaten the stability of

the grid, or when directed to do so by the SLDC/RLDC to prevent grid failure or during exigency conditions and for banking with other States on Short-term basis without prior approval of the Commission:

Provided that the details of such Short-term procurement shall be submitted to the Commission within 45 days from date of procurement of power with proper justification substantiating the emergency / exigency conditions.

Chapter 6

Monitoring and Compliance

19. Monitoring and Compliance

19.1. The Distribution Licensee(s) shall comply with the Resource Adequacy requirement in accordance with the timelines specified under Regulation 24 of these Regulations. In case of non-compliance, appropriate proceeding may be initiated against the Licensee(s) under the Act and penalty may be imposed.

19.2. The Distribution Licensee(s) shall not be allowed to recover, as part of its ARR, any penalty imposed due to the non-compliance.

19.3. Based on the LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP, STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity shortfall to the State Commission within 15 days of the receipt of approved Resource Adequacy Plan from the Distribution Licensee(s) of each year for the ensuing year(s) and advise the Distribution Licensee(s) to commit additional capacities.

At the end of each Financial Year, SLDC shall submit the deviation in RAR plan from actual demand profile during that financial year to the Commission and also upload such details on its website.

Chapter 7

Roles and Responsibilities

20. Data Requirement and Sharing Protocol

20.1. Distribution Licensee(s) shall maintain and share all data related to demand assessment and forecasting with the STU/SLDC, such as:-

a) Consumer data;

b) Historical demand data;

c) Weather data;

d) Demographic and econometric variables;

e) Distribution Losses and intra/inter-State Transmission losses;

f) Actual energy requirement;

g) Availability including curtailment, peak electricity demand, and peak met along with changes in demand profile (e.g.: agricultural shift, time of use, etc.); and

h) Historical hourly load pattern, etc.

20.2. Distribution Licensee(s) shall maintain and share all statistics and database pertaining to policies and drivers with SLDC, such as:-

a) LED penetration, efficient fan/ACs penetration, appliance penetration, increased usage of electrical appliances for cooking, heating, cooling, etc., in households;

b) Increase in commercial activities for geographic areas/regions;

c) Increase in number of agricultural pumps;

d) Solarization within Distribution Licensees' area;

e) Changes in specific energy consumption;

f) Consumption pattern from seasonal consumers;

g) Demand Side Management;

h) Distributed Energy Resources (DERs);

i) Electric Vehicles (EVs);

j) Open Access (OA);

k) National Hydrogen Mission;

l) Reduction of AT&C losses, etc:

Provided that statistics and database pertaining to households such as LED penetration, efficient fan penetration, appliance penetration, increased usage of electrical appliances for cooking, etc., shall be utilized by SLDC whenever statistical information and database become available through Distribution Licensee(s).

20.3. The Distribution Licensee(s) shall maintain at least past 10 years of statistics in their database pertaining to consumption profiles for each class of consumers, such as domestic, commercial, public lighting, public water works, agricultural/irrigation, LT industries, HT

industries, railway traction, bulk (non-industrial HT consumers), open access, captive power plants, insights from load survey, contribution of consumer category to peak demand, seasonal variation aspects, etc., and share the same with SLDC.

20.4. SLDC shall maintain the Distribution Licensee(s)-specific as well as aggregate for State as a whole, statistics and database pertaining to aggregate demand assessment and forecasting data as mentioned above and share State-level assessment with the Authority/NLDC and RLDC for regional/national assessment from time to time.

20.5. The Distribution Licensee(s) shall share information and data pertaining to the existing and contracted capacities with their technical and financial characteristics including hourly generation profiles to SLDC for computation of State-level capacity credit factors and for preparation of State-level assessment.

20.6. SLDC and the Distribution Licensee(s) shall aggregate generation data and share State-level projections with the Authority and NLDC as the case may be for assessment of Resource Adequacy requirement.

Chapter 8

Miscellaneous and Timelines

21. Placing of information on websites

21.1. The monthly/weekly/day-ahead/intra-day power procurements/sale by the Distribution Licensee(s) and generator schedule shall be made available on the websites of the Distribution Licensee(s) and SLDC latest by the end of ensuing month of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data.

21.2. SLDC shall prepare and also publish the monthly Merit Order Despatch (MoD) stack along with per unit variable cost of each generating station on its website, on the basis of the information provided by Distribution Licensee(s).

22. Constitution of dedicated cells

22.1. The Distribution Licensee(s) shall establish a planning cell for Resource Adequacy within three months of these Regulations coming into force. The cell shall have the requisite capability and tools for demand forecast, capacity, RE integration, etc.

22.2. Another round the clock dedicated cell shall also be constituted by the Distribution Licensee(s) for power purchase/sale of power on real-time basis and to also undertake intra-

day, day-ahead, week-ahead power procurement through Power Exchanges or any other means.

22.3. The Distribution Licensee(s) shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cells required under Sub-regulation (1) and (2) above, in line with the spirit of these Regulations and shall get the same approved by the Commission within 45 days from the date of coming into force of these Regulations.

23. Assessment to involve consultation

23.1. The Distribution Licensee(s) shall make the Resource Adequacy Plan in consultation with State Sector Generating Companies, Distribution Licensee(s), Central Sector Generating Companies, Transmission Companies, National / Regional /State Load Despatch Centre, and Central Electricity Authority. It shall also make enquiries with the Trading Companies and States with surplus power to estimate the likely availability and price of power across the country for peak, off-peak and normal periods. The Distribution Licensee(s) may also consult with research agencies with relevant experience.

24. Timelines

24.1. The SLDC shall be responsible for providing Deviation Settlement Mechanism (DSM) accounts to the Distribution Licensee(s) of previous financial year latest by 21st April of each year, and the Distribution Licensee(s) shall utilize the same for preparing its forecasts *[refer Regulation 6.3]*.

24.2. The Distribution Licensee(s) shall estimate and prepare hourly or sub-hourly 1-year Short-term (ST), 5-year Medium-term (MT) and 10-year Long-term (LT) demand forecasts at State Periphery on a rolling basis and submit the same to SLDC by 30th April of each year for the ensuing year(s) *[refer Regulation 8.1]*.

24.3. SLDC shall submit the state-level aggregate demand forecasts (MW and MUs) for Long-Term, Medium-Term and Short-Term to the Authority, NLDC, NRLDC, STU by 31st May of each year for the ensuing year(s) *[refer Regulation 8.3]*.

24.4. The Distribution Licensee(s) shall share CC factors for their contracted resources alongwith justification for its computations with SLDC by 15th May of each year for the ensuing year(s) *[refer Regulation 10.6]*.

24.5. SLDC shall calculate state-specific CC factors considering the aggregate State Demand and State Net Load and contracted RE generation resources available in the State and shall submit

such CC factor information to the Authority, NLDC and NRLDC by 31st May of each year for ensuing year(s) *[refer Regulation 10.7]*.

24.6. Based on optimistic scenario, the Distribution Licensee(s) shall undertake development of Long-term, Medium-term, and Short-term Distribution Resource Adequacy Plan exercise to meet the Resource Adequacy target requirement. The Distribution Licensee(s) shall submit the RA plans (LT-DRAP, MT-DRAP & ST-DRAP) so developed to the Commission by 31st August of each year. The Distribution Licensee(s) shall also submit the RA Plans to the STU and SLDC for further examination so as to apprise the Commission as per these Regulations *[refer Regulation 12.5]*.

24.7. Based on the allocated share in national peak provided in LT-NRAP for the State, the Distribution Licensee(s) shall ascertain its share in the national peak within 15 days of the publication of LT-NRAP *[refer Regulation 12.6(b)]*.

24.8. The Distribution Licensee(s) shall submit the details of the contracted capacities for the ensuing year for meeting RAR of national peak to SLDC within 15 days from the date of approval by the Commission *[refer Regulation 12.6(f)]*.

24.9. SLDC shall aggregate the total contracted capacities at the State level and submit the information to the NLDC/NRLDC, under intimation to the Commission, within 15 days from the date of receipt from the Distribution Licensee(s) *[refer Regulation 12.6(f)]*.

24.10. The Distribution Licensee(s) shall submit the LT-DRAP plans to CEA by 30th September of each year for the ensuing year(s) for validation *[refer Regulation 12.6(n)]*.

24.11. The Distribution Licensee(s) shall submit the LT-DRAP plan duly vetted by CEA along with necessary supporting documents, formats and details for meeting the RAR to the Commission within 15 days from the date of receipt of CEA approval *[refer Regulation 12.6(o)]*.

24.12. Distribution Licensee(s) shall perform and submit the MT-DRAP and ST-DRAP to the Authority and the NLDC by 31st August of each year for the ensuing year(s) *[refer Regulation 12.7(b) & 12.8 (b)]*.

24.13. The Distribution Licensee(s) shall submit MT-DRAP and ST-DRAP along with LT-DRAP to the Commission for approval *[refer Regulation 12.7(c) & 12.8 (c)]*.

24.14. The Commission shall approve Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) of the Distribution Licensee(s) within 120 days of submission by the Distribution Licensee(s)

of the duly vetted Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) by CEA for the ensuing year(s) including annual rolling plans, as the case may be, upon taking into consideration various scenarios as well as allocation of Resource Adequacy requirement allocated to the State/Distribution Licensee(s) based on its contribution to the National/state peak respectively as determined by Authority/NLDC/RLDC and STU/SLDC, as the case may be *[refer Regulation 12.9]*.

24.15. The Distribution Licensee(s) shall engage in adoption of least cost modelling and optimization techniques and shall demonstrate the same in its overall power procurement planning exercise to be submitted to Commission for approval by 30th April of each Financial Year *[refer Regulation 14.2]*.

24.16. The Distribution Licensee(s) shall submit the state-level aggregated Annual Rolling Plan to NRLDC by 20th January of each year for the ensuing year(s) *[refer Regulation 15.5]*.

24.17. The details of Short-term procurement when faced with emergency conditions shall be submitted to the Commission within 45 days from date of procurement of power with proper justification *[refer Regulation 18(b)]*.

24.18. Based on the LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP, STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity shortfall to the State Commission within 15 days of the receipt of approved Resource Adequacy Plan from the Distribution Licensee(s) of each year for the ensuing year(s) and advise the Distribution Licensee(s) to commit additional capacities. *[refer Regulation 19.3]*.

24.19. The monthly/weekly/day-ahead/intra-day power procurements/sale by the Distribution Licensee(s) and generator schedule shall be made available on the websites of the Distribution Licensee(s) and SLDC latest by the end of ensuing month of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data *[refer Regulation 21.1]*.

24.20. The Distribution Licensee(s) shall establish a planning cell for Resource Adequacy within three months of these Regulations coming into force *[refer Regulation 22.1]*.

24.21. The Distribution Licensee(s) shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cells required under Regulation 22, in line with the spirit of these Regulations and shall get the same approved by the Commission within 45 days from the date of coming into force of these Regulations *[refer Regulation 22.3]*.

24.22. The Distribution Licensee(s) shall submit the category-wise consumption information of previous financial years and any other information as may be required by SLDC by 21st April of each year for the ensuing year(s).

24.23. The SLDC, on behalf of the Distribution Licensee(s) in the State, shall submit demand forecasts (peak and energy requirement) for the next 10 years, assessment of existing generation resources, CC factor information and such other details as may be required for the LT-NRAP to CEA and ST-NRAP to NLDC by 31st May of every year for ensuing year(s).

24.24. SLDC shall allocate each Distribution Licensee's share in the national peak within 15 days of the publication of LT-NRAP report of each year for the ensuing year(s).

24.25. The contracting for balance capacity shortfall as communicated by NLDC shall be completed by the end of March of each year for the ensuing year(s) by the Distribution Licensee(s).

24.26. The Distribution Licensee(s), after contracting the balance capacity shall submit the information to the Commission by 1st April of each year for the current year(s).

Provided that in case there is delay in communication by NLDC for balance capacity shortfall, the Distribution Licensee(s) may seek approval from the Commission for time extension for contracting the balance capacity by 25th March of each year.

24.27. The Commission shall, by a separate Order, annually specify the timelines for submission of relevant data by grid-connected entities and obligated entities, having regard to the requirements of the Distribution Licensee(s) for the purpose of undertaking Resource Adequacy Planning:

Provided that this clause shall not apply to such entities in respect of whom specific timelines have already been prescribed under any other clause of these Regulations.

24.28. For the ease of reference, the above-mentioned timelines have been compiled based on the entity responsible for the same, and the same is available in the Table given in **Annexure IV** to these Regulations.

25. Deviation from the Norms

25.1. The parametric norms considered for approval of the Resource Adequacy Plan and Power procurement plan thereof, may be determined in deviation from the norms specified in these Regulations. Provided that the reasons for deviation from the norms specified under these Regulations shall be recorded in writing.

26. Power to Relax

26.1. The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

27. Power to Remove Difficulties

27.1. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by an order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act and these Regulations, as may appear to be necessary for removing the difficulty/ difficulties.

28. Power to amend

28.1. The Commission may from time to time add, vary, alter, modify, or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

29. Repeal and Savings

29.1. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

29.2. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

29.3. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers, and functions in a manner it thinks fit.

By the order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary.

ANNEXURE -I

Methodology of Preparation of Resource Adequacy Plan with constraints

a) The hourly demand profile for the Distribution Licensee(s) shall be projected over the planning period by the Distribution Licensee(s), based on the forecasted values of annual energy requirement and peak demand trajectory. The annual energy requirement and peak demand shall be forecasted using the methods specified in Regulation 6.6 of these Regulations. The projected hourly demand for the future years shall be used as inputs into the model. The Distribution Licensee(s) shall ensure that the generation expansion planning model chosen is capable of simulating on an hourly chronological resolution[1]. This is necessary to capture the behaviour of the system with respect to ramping of conventional generation, profiles of RE generation, behaviour of energy storage, etc.

b) After establishment of demand profile for all future years, the model would undertake an optimization exercise to minimize the total system cost to meet the future demand adhering to all power system parameters. Following constraints should be considered while modelling by the Distribution Licensee(s):

- **Planning Reserve Margin / Resource Adequacy Requirement:** The Resource Adequacy Requirement (RAR) constraint shall ensure that the total Resource Adequacy (Generation capacity) of the Distribution Licensee(s) fulfils the Planning Reserve Margin as determined by CEA. The resource adequacy requirement for each Distribution Licensee(s) shall be computed as:

$$RAR = Contribution^{2}\ to\ forecasted\ national\ peak\ demand\ in\ GW \times (1 + PRM)$$

From the supply side, the RAR shall be the sum of the "firm capacity" or "capacity credits" of contracted / planned capacities (including renewables, storage, otherresources such as demand response) along with derated interconnection limits (imports)[3].

Both, supply side and demand side RAR shall match. The Thermal capacity credit shall be calculated by reducing the auxiliary consumption and the forced outage rate from the

[1] It is preferred to simulate all 8760 hours (8784 hours for leap year) on a chronological resolution in a year. However, if computational challenges are faced, the Distribution Licensee(s) can select the representative periods, which may be different. The representative periods chosen are reflective of various projected demand and supply profiles for the base year and future years. Initially, hourly simulation is planned based on hourly data availability, however, the time granularity may be increased to sub-hourly provided there is availability of sub-hourly demand and RE generation data.

[2] This shall be calculated as Distribution Licensee's demand at the time of national peak demand.

[3] The firm capacity shall be calculated as provided in Annexure-III of these regulations.

installed capacity.

The capacity credits for generating resources and demand response resources to meet the national peak shall be as estimated by CEA. The capacity credits published by CEA for each resource type may differ between existing and new resources and between resources in different regions. For example, a solar based power plant in the Southern Region will have a capacity credit, which could be different compared to a solar plant in the Northern Region. Similarly, an upcoming wind-based power plant could have a different capacity credit compared to an already commissioned wind plant in the same region. The Distribution Licensee(s) shall use these capacity credits for generation sources with which it has a PPA located outside the State, while planning to meet their RAR. For example, a Distribution Licensee having a PPA with an existing solar based power plant located in a southern State would use the capacity credit of existing solar based power plants in the Southern Region.

- **Portfolio balance constraints:** The portfolio balance shall ensure that the total generation within a control area of Region/State/Distribution Licensee(s) and the import of power to the control area of region/State/Distribution Licensee(s) is equal to the sum of the demand, exports from the control area of region/State/Distribution Licensee(s), any energy not served and curtailment, for each hour.

- **RE Generation constraints:** For renewable energy resources, such as solar and wind, the RE generation shall be constrained as per the hourly profile of the resource. Historic profiles of renewable sources shall be used to generate the hourly profiles. Additional constraints shall ensure that the Distribution Licensee's overall renewable generation targets are met and included while formulating LT-DRAP.

- **Conventional Generation constraints:**

  i. Unlike solar and wind, thermal resources are dispatchable. However, the thermal resources are bound by constraints such as maximum and minimum generation limits, ramp rates, spinning reserve offers, plant availability and unit commitment decisions.

  ii. The dispatch (energy offer) plus the reserve offer (specified through CERC/UERC Regulations) for each generator is constrained to be within the maximum and minimum generation limits. Generation between two consecutive time blocks also must be within the ramping capabilities of the resources. Unit commitment decisions, such as start-up/shut-down, minimum up and down times, etc., require binary variables to implement and are to be included. Additionally, generation units may have periods of outages, which may need to be captured by using an availability factor.

iii. The capacity for each year needs to be tracked by a constraint, which shall ensure that the capacity in a particular year is equal to the capacity last year plus any new capacity investment minus capacity retirement, if any.

- **RPO constraints:** Fulfilment of Renewable Purchase Obligation shall be considered as one of the objectives of Resource Adequacy. Technology options like renewable energy generation for round the clock energy supply backed with storage (Battery and PSP), standalone renewable energy capacity along with hydro capacity for balancing renewable energy generation shall be considered while carrying out resource adequacy exercise for Distribution Licensee(s).

- **Storage constraints:** Due to the intermittent nature of renewable energy generation, the need for resources, which can store surplus energy and despatch the stored energy during low RE generation periods becomes vital. Storage charge and discharge at any instant are constrained by the storage level or the state of charge (SoC) of the storage resource, and the maximum charge / discharge limit. The resource shall only discharge if there is sufficient energy present due to prior charging of the resource. To implement this, considering the chronological sequence of time is also important. Since, storage resources convert electricity to other forms of energy, there are also some efficiency losses (round-trip efficiency) which shall be accounted for. Different technologies may have different discharge periods (energy limits), power outputs (maximum charge / discharge) and levels of efficiency.

- **Operating (Spinning) Reserve constraints:** Operating reserve shall ensure that sufficient resources are in the system and kept online or on standby each hour to account for load forecast errors, intermittency of RE or meeting contingencies in real time. The thumb rule for operating reserve requirement shall be defined based on discussions with the SLDC and shall be considered as an input parameter to the model.

- **Demand Response:** Potential for demand side management such as shifting of load or demand response can be considered while undertaking the Resource Adequacy Plan (RAP). The constraints such as periods when load shifting can occur, and the maximum quantum of load, which can be shifted over a period shall be included.

ANNEXURE -II

Formats (1 to 13) enclosed separately

ANNEXURE -III

The firm capacity to meet the Resource Adequacy Requirement (RAR) shall be calculated as shown below:

$$RAR = \sum_{i=1}^{num\_solar} Solar\_Capacity * Solar\_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_wind} Wind\_Capacity * Wind\_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_hydro} Hydro\_Capacity * Hydro\_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_thermal} Thermal\_Capacity * Thermal\_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_nuclear} Nuclear\_Capacity * Nuclear\_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_storage} Storage\_Capacity * Storage\_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_other} Other\ Resource\_Capacity * Other\ Resource\ \_Capacity\_Credit + \sum_{i=1}^{num\_Other} Import\_limit * Capacity\_Credit$$

ANNEXURE -IV

Timelines prescribed under the Regulations

S.No.	Particulars	Timeline
A. Responsible Entity: State Commission		
A. 1	The Commission shall approve Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) of the Distribution Licensee(s) within 120 days of submission by the Distribution Licensee(s) of the duly vetted Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) by CEA for the ensuing year(s) including annual rolling plans, as the case may be, upon taking into consideration various scenarios as well as allocation of Resource Adequacy requirement allocated to the State/ Distribution Licensee(s) based on its contribution to the National/state peak respectively as determined by Authority/NLDC/RLDC and STU/SLDC, as the case may be [*refer Regulation 12.9*].	Within 120 days of submission by the Distribution Licensee(s) of the Resource Adequacy Plan (LT-DRAP, MT-DRAP, ST-DRAP) duly-vetted by CEA.
A. 2	The Commission shall, by a separate Order, annually specify the timelines for submission of relevant data by grid-connected entities and obligated entities, having regard to the requirements of the Distribution Licensee(s) for the purpose of undertaking Resource Adequacy Planning: Provided that this clause shall not apply to such entities in respect of whom specific timelines have already been prescribed under any other clause of these Regulations.	Annually, by a separate Order.
B. Responsible Entity: Distribution Licensee(s)		
B.1	The Distribution Licensee(s) shall estimate and prepare hourly or sub-hourly 1-year Short-term (ST), 5-year Medium-term (MT) and 10-year Long-term (LT) demand forecasts at State Periphery on a rolling basis and submit the same to SLDC by 30th April of each year for the ensuing year(s) [*refer Regulation 8.1*].	By 30th April of each year.
B.2	The Distribution Licensee(s) shall share CC factors for their contracted resources alongwith justification for its computations with SLDC by 15th May of each year for the ensuing year(s) [*refer Regulation 10.6*].	By 15th May of each year.
B.3	Based on optimistic scenario, the Distribution Licensee(s) shall undertake development of Long-term, Medium-term, and Short-term Distribution Resource Adequacy Plan exercise to meet the Resource Adequacy target requirement. The Distribution Licensee(s) shall submit the RA plans (LT-DRAP, MT-DRAP & ST-DRAP) so developed to the Commission by 31st August of each year. The Distribution Licensee(s) shall also submit the RA Plans to the STU and SLDC for further examination so as to apprise the Commission as per these Regulations [*refer Regulation 12.5*].	By 31st August of each year.
B.4	Based on the allocated share in national peak provided in LT-NRAP for the State, the Distribution Licensee(s) shall ascertain its share in the national peak within 15 days of the publication of LT-NRAP [*refer Regulation 12.6(b)*].	Within 15 days of the publication of LT-NRAP.

Timelines prescribed under the Regulations

S.No.	Particulars	Timeline
B.5	The Distribution Licensee(s) shall submit the details of the contracted capacities for the ensuing year for meeting RAR of national peak to SLDC within 15 days from the date of approval by the Commission [*refer Regulation 12.6(f)*].	Within 15 days from the date of approval by the Commission.
B.6	The Distribution Licensee(s) shall submit the LT-DRAP plans to CEA by 30th September of each year for the ensuing year(s) for validation [*refer Regulation 12.6(n)*].	By 30th September of each year.
B.7	The Distribution Licensee(s) shall submit the LT-DRAP plan duly vetted by CEA along with necessary supporting documents, formats and details for meeting the RAR to the Commission within 15 days from the date of receipt of CEA approval [*refer Regulation 12.6(o)*].	Within 15 days from the date of receipt of CEA approval.
B.8	Distribution Licensee(s) shall perform and submit the MT-DRAP and ST-DRAP to the Authority and the NLDC by 31st August of each year for the ensuing year(s) [*refer Regulation 12.7(b) & 12.8 (b)*].	By 31st August of each year.
B.9	The Distribution Licensee(s) shall submit MT-DRAP and ST-DRAP along with LT-DRAP to the Commission for approval [*refer Regulation 12.7(c) & 12.8 (c)*].	Along with LT-DRAP.
B.10	The Distribution Licensee(s) shall engage in adoption of least cost modelling and optimization techniques and shall demonstrate the same in its overall power procurement planning exercise to be submitted to Commission for approval by 30th April of each Financial Year [*refer Regulation 14.2*].	By 30th April of each Financial Year.
B.11	The Distribution Licensee(s) shall submit the state-level aggregated Annual Rolling Plan to NRLDC by 20th January of each year for the ensuing year(s) [*refer Regulation 15.5*].	By 20th January of each year.
B.12	The details of Short-term procurement when faced with emergency conditions shall be submitted to the Commission within 45 days from date of procurement of power with proper justification [*refer Regulation 18(b)*].	Within 45 days from the date of procurement of power.
B.13	The monthly / weekly / day-ahead / intra-day power procurements / sale by the Distribution Licensee(s) and generator schedule shall be made available on the websites of the Distribution Licensee(s) and SLDC latest by the end of ensuing month of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data [*refer Regulation 21.1*].	Latest by the end of ensuing month of procurements/sale of power.
B.14	The Distribution Licensee(s) shall establish a planning cell for Resource Adequacy within three months of these Regulations coming into force [*refer Regulation 22.1*].	Within three months of the notification of the Regulations.
B.15	The Distribution Licensee(s) shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cells required under Regulation 22, in line with the spirit of these Regulations and shall get the same approved by the Commission within 45 days from the date of coming into force of these Regulations [*refer Regulation 22.3*].	Seek approval of the Commission within 45 days from the date of notification of the Regulations.

Timelines prescribed under the Regulations

S.No.	Particulars	Timeline
B.16	The Distribution Licensee(s) shall submit the category-wise consumption information of previous financial years and any other information as may be required by SLDC by 21st April of each year for the ensuing year(s).	By 21st April of each year.
B.17	The contracting for balance capacity shortfall as communicated by NLDC shall be completed by the end of March of each year for the ensuing year(s) by the Distribution Licensee(s).	By the end of March of each year.
B.18	The Distribution Licensee(s), after contracting the balance capacity shall submit the information to the Commission by 1st April of each year for the current year(s). Provided that in case there is delay in communication by NLDC for balance capacity shortfall, the Distribution Licensee(s) may seek approval from the Commission for time extension for contracting the balance capacity by 25th March of each year.	By 1st April of each year (in case of delay by NLDC time extension may be sought by 25th March of each year).
C. Responsible Entity: SLDC/STU		
C.1	The SLDC shall be responsible for providing Deviation Settlement Mechanism (DSM) accounts to the Distribution Licensee(s) of previous financial year latest by 21st April of each year, and the Distribution Licensee(s) shall utilize the same for preparing its forecasts [*refer Regulation 6.3*].	Latest by 21st April of each year.
C.2	SLDC shall submit the state-level aggregate demand forecasts (MW and MUs) for Long-Term, Medium-Term and Short-Term to the Authority, NLDC, NRLDC, STU by 31st May of each year for the ensuing year(s) [*refer Regulation 8.3*].	By 31st May of each year.
C.3	SLDC shall calculate state-specific CC factors considering the aggregate State Demand and State Net Load and contracted RE generation resources available in the State and shall submit such CC factor information to the Authority, NLDC and NRLDC by 31st May of each year for ensuing year(s) [*refer Regulation 10.7*].	By 31st May of each year.
C.4	SLDC shall aggregate the total contracted capacities at the State level and submit the information to the NLDC/NRLDC, under intimation to the Commission, within 15 days from the date of receipt from the Distribution Licensee(s) [*refer Regulation 12.6(f)*].	Within 15 days from the date of receipt from the Distribution Licensee(s).
C.5	Based on the LT-DRAP, MT-DRAP and ST-DRAP, STU and SLDC shall communicate the state-aggregated capacity shortfall to the State Commission within 15 days of the receipt of approved Resource Adequacy Plan from the Distribution Licensee(s) of each year for the ensuing year(s) and advise the Distribution Licensee(s) to commit additional capacities. [*refer Regulation 19.3*].	Within 15 days of the receipt of the approved Resource Adequacy Plan.
C.6	The monthly/weekly/day-ahead/intra-day power procurements / sale by the Distribution Licensee(s) and generator schedule shall be made available on the websites of the Distribution Licensee(s) and SLDC latest by the end of ensuing month of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data [*refer Regulation 21.1*].	Latest by the end of ensuing month of procurements/sale of power.

Timelines prescribed under the Regulations

S.No.	Particulars	Timeline
C.7	The SLDC, on behalf of the Distribution Licensee(s) in the State, shall submit demand forecasts (peak and energy requirement) for the next 10 years, assessment of existing generation resources, CC factor information and such other details as may be required for the LT-NRAP to CEA and ST-NRAP to NLDC by 31st May of every year for ensuing year(s).	By 31st May of every year.
C.8	SLDC shall allocate each Distribution Licensee's share in the national peak within 15 days of the publication of LT-NRAP report of each year for the ensuing year(s).	Within 15 days of the publication of the LT-NRAP report.

Annexure-II

Demand Forecast (Summary Statement for State)									*Format-1*
Sr. No.	Particulars	Actual of Previous Years			Current Year (n)	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)	Projections		
		Yr (n-3)	Yr (n-2)	Yr (n-1)			Yr (n+1)	Yr (n+2)	...Yr (n+10)
1	Energy Sale - MUs *(Consumer Category wise as per Retail Supply Tariff Order)*								
	Domestic								
	Non-Domestic								
	Public Water Works & Street Light								
	Agriculture and Allied Activities								
	LT Industries								
	HT Industries								
	Contracted Load up to 1000 kVA:								
	- Load Factro Upto 50%								
	- Load Factro Above 50%								
	Contracted Load More than 1000 kVA:								
	- Load Factro Upto 50%								
	- Load Factro Above 50%								
	Mixed Load								
	Railway Traction								
	Electric Vehicle Charging Stations								
	Others Category 1								
	Others Category 2								
	Others Category 3								
2	Total Energy Sale (MU)- *(Cumulative of all consumer categories)*								
3	*YoY growth rate for total energy Sales (%)*								
4	Distribution losses - in %								
5	Distribution losses - in MU								
6	Supply / Requirement at DISCOM Boundary(MU)								
7	Intra-State Transmission losses - in %								
8	Intra-State Transmission losses - in MU								
9	Supply / Requirement at State Boundary(MU)								
10	Inter-State Transmission losses - in %								
11	Inter-State Transmission losses - in MU								
12	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU)								
13	*Sale by UPCL to Outside State*								
14	*Energy Wheeled for OA Consumers*								
15	Ex-Bus Requirement of State (MU)								
16	Peak load of DISCOM (MW)								
17	Peak load of State (MW)								
Note:	*1. The Demand Forecast would be supported by Graphs showing yearly Demand Pattern for Consumer Category and wherever possible sample 24hr Load Duration Curve also needs to be provided.*								
	2. The Demand Forecast shall be done in accrdance with Regulation 6 of the UERC (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2026.								
	3. The above format for furnishing information related to Demand Forecasting is subject to change if methodology adopted for Demand Forecasting is other than Partial End Use method (PEUM).								

Demand Forecast (Summary Statement for State)									Format-1A
Sr. No.	Particulars	Actual of Previous Years			Current Year (n)	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)	Projections		
		Yr (n-3)	Yr (n-2)	Yr (n-1)			Yr (n+1)	Yr (n+2)	...Yr (n+10)
1	Contract Demand - MW (Consumer Category wise as per Retail Supply Tariff Order)								
	Domestic								
	Non-Domestic								
	Public Water Works & Street Light								
	Agriculture and Allied Activities								
	LT Industries								
	HT Industries								
	Contracted Load up to 1000 kVA:								
	- Load Factro Upto 50%								
	- Load Factro Above 50%								
	Contracted Load More than 1000 kVA:								
	- Load Factro Upto 50%								
	- Load Factro Above 50%								
	Mixed Load								
	Railway Traction								
	Electric Vehicle Charging Stations								
	Others Category 1								
	Others Category 2								
	Others Category 3								
2	Total Contracted Demand (MW)- (Cumulative of all consumer categories)								
3	YoY growth rate for Contracted Demand (%)								
4	Ex-Bus Requirement of State (MU)								
5	Peak load of DISCOM (MW)								
6	Peak load of State (MW)								
Note:	*1. The Demand Forecast would be supported by Graphs showing yearly Demand Pattern for Consumer Category and wherever possible sample 24hr Load Duration Curve also needs to be provided.*								
	2. The Demand Forecast shall be done in accrdance with Regulation 6 of the UERC (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2026.								
	3. The above format for furnishing information related to Demand Forecasting is subject to change if methodology adopted for Demand Forecasting is other than Partial End Use method (PEUM).								

Monthly Ex-Bus Energy Requirement (MU)							*Format-2*
Month	Actual of Previous Years			Projections			
	Yr (n-3)	Yr (n-2)	Yr (n-1)	Current Year (n)	Yr (n+1)	Yr (n+2)	...Yr (n+10)
State (DISCOM including OACs)							
Apr							
May							
Jun							
Jul							
Aug							
Sep							
Oct							
Nov							
Dec							
Jan							
Feb							
Mar							
DISCOM							
Apr							
May							
Jun							
Jul							
Aug							
Sep							
Oct							
Nov							
Dec							
Jan							
Feb							
Mar							
Open Access Consumers (OACs)							
Apr							
May							
Jun							
Jul							
Aug							
Sep							
Oct							
Nov							
Dec							
Jan							
Feb							
Mar							

Power Supply Projections						Format-3
No.	Particulars	Projections				
		Yr (n+1)	Yr (n+2)	Yr (n+3)	Yr (n+4)	...Yr (n+10)
1	Ex-Bus Requirement of State (MU)					
	For DISCOMs (MU)					
	For Sale by UPCL to Outside State					
	For OA (MU)					
2	Energy Availability (MU)					
	Uttarakhand State Genco Hydel Plants					
	Uttarakhand State Gas based Plants					
	Central Sector Stations					
	Medium/Long Term tie-ups					
	Other IPPs					
	Solar Generators Availability					
	Availability through PSP					
	Availability through BESS					
	Availability through banking/Power Market					
	Others Sources (If any)					
	TOTAL (MU)					
3	*Surplus(+)/Deficit(-) (MU)*					
4	*Surplus(+)/Deficit(-)(%)*					
Note:	*1. The yearly Energy requirement/Supply should tally with monthly requirement/supply forecast as indicated in Format-2*					
	2. The Power Supply Position would be supported by Graphs showing yearly and Monthly Pattern					

Peak Demand and Availability Projections						*Format-4*
(Peak Hours/Off-Peak Hours)						
No.	Particulars	Projections				
		Yr (n+1)	Yr (n+2)	Yr (n+3)	Yr (n+4)	...Yr (n+10)
1	Available Generation Capacity (MW)					
	Uttarakhand State Genco Hydel Plants					
	Uttarakhand State Gas based Plants					
	Central Sector Stations					
	Medium/Long Term tie-ups					
	Other IPPs					
	Solar Generators Availability					
	Availability through PSP					
	Availability through banking/Power Market					
	Others Sources (If any)					
	TOTAL (MW)					
2	Peak Load of State (MW)					
3	Peak Availability (MW)					
	Uttarakhand State Genco Hydel Plants					
	Uttarakhand State Gas based Plants					
	Central Sector Stations					
	Medium/Long Term tie-ups					
	Other IPPs					
	Solar Generators Availability					
	Availability through PSP					
	Availability through BESS					
	Availability through banking/Power Market					
	Others Sources (If any)					
	TOTAL (MW)					
4	*Surplus(+)/Deficit(-) (MW)*					
5	*Surplus(+)/Deficit(-) (%)*					
Note:	*1. This format is to be submitted for Peak Hours and Off-Peak Hours Separately.*					
	2. The Power Supply Position needs to be supported by Graphs showing yearly or monthly 24 hr load pattern based on Load Research by the Company.					
	3. Peak Hours and Off-Peak Hours shall be as specified in the Retail Supply Tariff Order.					

Available/Existing Generation Capacities and Year wise Energy Availability								Format-5
No.	Name of Plant	COD	Capacity (MW)	State Share (MW)	Energy Availabilty (MU)			
					Yr (n+1)	Yr (n+2)	Yr (n+3)	...Yr (n+10)
1	Uttarakhand State Genco Hydel Plants							
2	Uttarakhand State Gas based Plants							
3	Central Sector Stations							
4	Medium/Long Term tie-ups							
5	Other IPPs							
6	Solar Generators Availability							
7	Availability through PSP							
8	Availability through banking/Power Market							
9	Availability through BESS							
10	*Others Sources (If any)*							
Total								
Note:	*1. This format is to be submitted Separately for Long-Term/Medium-Term/Short-Term.*							
	2. The above format needs to be filled considering the plant wise availablility of each State/Central Generating plants, IPPs, Renewable plants and other Plants for entire 10-year plan.							

Details of Planned/Upcoming Capacities for future years alongwith Energy Availability — *Format-6*

No.	Name of Project	Capacity (MW)	State Share (MW)	SCOD	Year wise Capacity Addition (MW)				Energy Availabilty (MU)			
					Yr (n+1)	Yr (n+2)	Yr (n+3)	...Yr (n+10)	Yr (n+1)	Yr (n+2)	Yr (n+3)	...Yr (n+10)
1	Uttarakhand State Genco Hydel Plants											
2	Uttarakhand State Gas based Plants											
3	Central Sector Stations											
4	Medium/Long Term tie-ups											
5	Other IPPs											
6	Solar Generators Availability											
7	Availability through PSP											
8	Availability through BESS											
9	Availability through banking/Power Market											
10	Others Sources (If any)											
Total												

Note:

1. *This format is to be submitted Separately for Long-Term/Medium-Term/Short-Term.*
2. *The above format needs to be filled considering the plant wise availablility of each State/Central Generating plants, IPPs, Renewable plants and other Plants for entire 10-year plan.*

Month-Wise Energy Availabilty from Available/Exisitng Generation Capacities — *Format-7*

No.	Name of Project	Monthly Energy Availabilty (MU)											
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	Uttarakhand State Genco Hydel Plants												
2	Uttarakhand State Gas based Plants												
3	Central Sector Stations												
4	Medium/Long Term tie-ups												
5	Other IPPs												
6	Solar Generators Availability												
7	Availability through PSP												
8	Availability through BESS												
9	Availability through banking/Power Market												
10	Others Sources (If any)												
Total													

Note:

1. *This format is to be submitted Separately for Long-Term/Medium-Term/Short-Term.*
2. *This format is to be furnished year-wise for entire 10-years separately*
3. *The above format needs to be filled considering the plant wise availablility of each State/Central Generating plants, IPPs, Renewable plants and other Plants for entire 10-year plan.*

Month-Wise Energy Availabilty from Planned/Upcoming Generation Capacities — *Format-8*

No.	Name of Project	Monthly Energy Availabilty (MU)											
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	Uttarakhand State Genco Hydel Plants												
2	Uttarakhand State Gas based Plants												
3	Central Sector Stations												
4	Medium/Long Term tie-ups												
5	Other IPPs												
6	Solar Generators Availability												
7	Availability through PSP												
8	Availability through BESS												
9	Availability through banking/Power Market												
10	Others Sources (If any)												
Total													

Note:

1. *This format is to be submitted Separately for Long-Term/Medium-Term/Short-Term.*
2. *This format is to be furnished year-wise for entire 10-years separately.*
3. *The above format needs to be filled considering the plant wise availablility of each State/Central Generating plants, IPPs, Renewable plants and other Plants for entire 10-year plan.*

Summary of Month wise Energy Requirement and Energy Availability (MU)													*Format-9*
No.	Particulars	Monthly Energy Availabilty (MU)											
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	Yr (n+1)												
	Energy Requirement												
	Energy Availability												
	Surplus(+)/Deficit(-) (MU)												
	Surplus(+)/Deficit(-)(%)												
2	Yr (n+2)												
	Energy Requirement												
	Energy Availability												
	Surplus(+)/Deficit(-) (MU)												
	Surplus(+)/Deficit(-)(%)												
3	Yr (n+3)												
	Energy Requirement												
	Energy Availability												
	Surplus(+)/Deficit(-) (MU)												
	Surplus(+)/Deficit(-)(%)												
..... 10	.....Yr (n+10)												
	Energy Requirement												
	Energy Availability												
	Surplus(+)/Deficit(-) (MU)												
	Surplus(+)/Deficit(-)(%)												
Note:	*1.This format figures should tally with Format-2, Format-7 and Format-8.*												
	2. This format is to be furnished year-wise for entire 10-years separately.												
	3. The above format needs to be filled considering the plant wise availablility of each State/Central Generating plants, IPPs, Renewable plants and other Plants for entire 10-year plan.												

Generating Stations Details

Format-10

Sr. No.	Name of Generating Station	Region /State	Installed capacity (MW)	Share of Uttarakhand (%)	COD/ SCOD	Expected Retirement Year	Fixed Cost (Rs/MW)	Variable Cost (Rs/kWh)	Auxiliary Consumption (%)	Max Generation Limits (MW)	Min Generation Limits (MW)	Fuel GCV (GJ/kg)	Heat Rate (at full Load)	Heat rate (at part load i.e. 55%)	Ramp Up rate (MW/min)	Ramp down rate (MW/min)

Continued...

Format-10 (A)

Generating Stations Details													
Plant Availbility Factor (in %) in case of Thermal and Hydro/ Capacity Utulisation Factor for renewable based resources	Design Energy in case of Hydro (MU)	Start-up Cost (Rs. Crore)	Start-up time (Hours)	Backdown Compention Cost (Rs. Crore)	Planned Maintenance (Hours)	Forced Outage (Hours)	Mode of Operation (PPA/MOD/ Must Run)	Storage (In case of Hydro & PSP) (in MWh)	Investment Cost (Rs./Crore/MW)	Date of signing of PPA	Date of Expiry of PPA	Type of Capacity (Existing/ Planned/Addition)	Contract Type (Long-Term/Medium Term and Short Term)

Plan for Renewable Power Obligation (RPO)

Format-11

Particulars		Unit	Projection				
			Yr (n+1)	Yr (n+2)	Yr (n+3)	Yr (n+4)	...Yr (n+10)
Ex-Bus Energy Requirement (MU) (DISCOMs)		MU					
Wind RPO (by WPPs commissioned after 31st March 2022)	RPO	%					
	RPO	MU					
	Availability from Qualified Tied up (including consented) projects						
	Availability from Wind Component of RE RTC projects						
	Year wise Balance RPO quantum to be met						
	Additional Capacity required up to fulfill RPO	MW					
HPO (by Hydro projects commissioned after 8th March 2019)	RPO	%					
	RPO	MU					
	Availability from Qualified Tied up (including consented) projects						
	Year wise Balance RPO quantum to be met						
	Additional Capacity required up to fulfill RPO	MW					
Distributed RPO (Distributed renewable energy component shall be met only from the energy generated from renewable energy projects that are less than 10 MW in size and shall include solar installations under all configuration (niet metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installation and any other configuration) notified by the Central Government)	RPO	%					
	RPO	MU					
	Availability from Qualified Tied up (including consented) projects						
	Availability from Solar Component of RE RTC projects						
	Year wise Balance RPO quantum to be met						
	Additional Capacity required up to fulfill RPO	MW					
Other RPO (Other RPO shall be met by energy produced from any RE power project not mentioned in (2), (3) and (4) above and shall comprise energy from all Wind Power Projects, HPPs (including PSPs and SHPs) including free power)	RPO	%					
	RPO	MU					
	Old WPP's Contribution						
	Old Hydro Project's Contribution						
	Other Solar Contribution						
	Total Contribution from Tied up Projects						
	Remaining RPO Quantum						
	Additional Capacity required up to fulfill RPO	MW					
Total RPO	RPO	%					
	RPO	MU					
	RPO	MW					
ESO	Energy Storage Obligation	%					
	Energy to be procured through Storage	MU					
	Energy to be procured through Storage	MW					

Deviation in Demand Forecast (Summary Statement for State.)					*Format-12*
Sr. No.	Particulars	Previous Years approved As per Plan (1)	Actual (2)	Deviation (2-1)	Reasons for deviation
1	Total Energy Sale (MU)- *(Cumulative of all consumer categories)*				
2	Distribution losses - in %				
3	Distribution losses - in MU				
4	Supply / Requirement at DISCOM Boundary(MU)				
5	Intra-State Transmission losses - in %				
6	Intra-State Transmission losses - in MU				
7	Supply / Requirement at State Boundary(MU)				
8	Inter-State Transmission losses - in %				
9	Inter-State Transmission losses - in MU				
10	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU)				
11	*Sale by UPCL to Outside State*				
12	*Energy Wheeled for OA Consumers*				
13	Ex-Bus Requirement of State (MU)				
14	Peak load of DISCOM (MW)				
15	Peak load of State (MW)				

Deviation in Energy Availability					*Format-13*
Sr. No.	Particulars	Previous Years approved As per Plan (1)	Actual (2)	Deviation (2-1)	Reasons for deviation
1	Ex-Bus Requirement of State (MU)				
	For DISCOMs (MU)				
	For Sale by UPCL to Outside State				
	For OA (MU)				
2	Energy Availability (MU)				
	Uttarakhand State Genco Hydel Plants				
	Uttarakhand State Gas based Plants				
	Central Sector Stations				
	Medium/Long Term tie-ups				
	Other IPPs				
	Solar Generators Availability				
	Availability through PSP				
	Availability through BESS				
	Availability through banking/Power Market				
	Others Sources (If any)				
3	TOTAL (MU)				

By the order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/294–भाग 1–क–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2026 ई0 (श्रावण 17, 1948 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं0) बागेश्वर

अधिसूचना की सूचना

07 जुलाई, 2026 ई0

पत्रांक 590/पंचा0चुना0/सा0निर्वा0/उप प्रधान/2026–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–412/रा0नि0आ0–2/4723/2026 दिनांक 06 जुलाई, 2026 के क्रम में मैं अपूर्वा पाण्डे, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), बागेश्वर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद बागेश्वर के विकास खण्डों के समस्त ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन हेतु निम्नांकित विर्निदिष्ट समय–सारणी के अनुसार कराये जाने हेतु अधिसूचित करती हूँ :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिह्न आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
15.07.2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	15.07.2026 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	15.07.2026 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	15.07.2026 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	15.07.2026 (अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक)	15.07.2026 (अपराह्न 04:00 बजे से कार्य कर समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जॉच, नाम वापसी, निर्वाचन चिह्न (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के लिए इस अधिसूचना की सूचना में मतदान हेतु विर्निदिष्ट दिनांक 15.07.2026 को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 08 जुलाई,2026 से दिनांक 14 जुलाई,2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक तथा तदोपरान्त दिनांक 15 जुलाई,2026 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से 09:30 बजे तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत में विर्निदिष्ट स्थान पर की जायेगी। नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री की सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा गांवो में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

अपूर्वा पाण्डे,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)
बागेश्वर।

प्रारूप– क

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	उप प्रधान ग्राम पंचायतों की संख्या
01	बागेश्वर	182	182
02	कपकोट	122	122
03	गरूड़	101	101

अपूर्वा पाण्डे,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/294–भाग 3–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 अगस्त, 2026 ई0 (श्रावण 17, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे पुत्र SHIVAM YADAV के वर्ष–2019 हाईस्कूल अनुक्रमांक 5309747 व वर्ष 2021 इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25610656 में त्रुटिवश पिता का नाम पवन यादव (PAWAN YADAV) गलत दर्ज हो गया है। जबकि पिता का सही नाम पवन कुमार यादव (PAWAN KUMAR YADAV) हैं।जो पिता के आधार कार्ड नं0 4931 8432 1740 व पेन कार्ड नं. ADVPY8190R में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को SHIVAM YADAV S/o पवन कुमार यादव (PAWAN KUMAR YADAV) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

पवन कुमार यादव (PAWAN KUMAR YADAV)
निवासी–गली नं0 15, ग्राम अपर नत्थनपुर नेहरूग्राम
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र APAAR AGGARWAL के वर्ष 2024 के CBSE हाईस्कूल अनुक्रमांक 25106496 में त्रुटिवश माता का अग्रेजी में नाम MEENU AGGARWAL के स्थान पर MEENU AGGRAWAL गलत दर्ज हो गया है, जबकि माता का अग्रेजी में सही नाम MEENU AGGARWAL है। जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण सं. 20080606040 एवं माता के आधार कार्ड नं. 835980246226 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को APAAR AGGARWAL S/o MEENU AGGARWAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MEENU AGGARWAL W/O DEEPAK AGGARWAL
निवासी–14, कचहरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2549 3506 0245 में त्रुटिवश उसका नाम LAXMI दर्ज हो गया है, जबकि उसका वास्तविक नाम LAKSHMI है। मेरी पुत्री का सही नाम LAKSHMI ही है, जो उसकी हाईस्कूल अंकतालिका अनुक्रमांक संख्या 24031762 एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या UK26 ES0100004234 में दर्ज है। अतः भविष्य में मेरी पुत्री को LAKSHMI D/O GULAB CHAND के नाम से ही जाना व पहचाना जाए। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

गुलाबचंद
निवासी–केशवपुरी, डोईवाला जिला देहरादून।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड सं. 856101912161 में उसका नाम विराज सिंघल (VIRAJ SINGHAL) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैनें अपने पुत्र का नाम विराज सिंघल (VIRAJ SINGHAL) से बदलकर हितांश सिंघल (HETANSH SINGHAL) कर लिया है जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या B–2019:5–90069–000446 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को हितांश सिंघल (HETANSH SINGHAL) पुत्र श्री मंयक सिंघल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

मंयक सिंघल
निवासी– म. न.–243, लेन नं0 5, रामनगर,
रुड़की, जिला–हरिद्वार, राज्य– उत्तराखण्ड–247667.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 7412 5856 6710 में त्रुटिवश मेरा नाम महेश्वरी देवी (Maheshwari Devi) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम महेशा देवी (Mahesha Devi) है। जो मेरे जन्म प्रमाण–पत्र पंजी सं0 व B20260503001000007 स्थाई निवास प्रमाण–पत्र पंजी सं0 UK26ES0100151479 व पति के आर्मी रिकार्ड में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे महेशा देवी (Mahesha Devi) पत्नी स्व0 सुल्तान सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

महेशा देवी (Mahesha Devi) पत्नी स्व0 सुल्तान सिंह
निवासी–जवाडी चिपलघाट पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 5645 6953 4683 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम मनीषा (MANISHA) एवं पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र पंजी सं0 1116 में उसका नाम मनीषा उर्फ मानसी (MANISHA URF MANSI) दर्ज है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम मानसी (MANSI) है। जो पुत्री के कक्षा–5 के पंजिका सं0 1403 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को मानसी (MANSI) पुत्री श्री विककी कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

विककी कुमार
निवासी असफ नगर हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 450102146589 में त्रुटिवश उसका हिन्दी एवं अग्रेजी में नाम प्रज्ञा सैनी (PRAGYA SAINI) के स्थान पर परिगगया (PARIGGYA) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रज्ञा सैनी (PRAGYA SAINI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B202509000050000041 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को प्रज्ञा सैनी (PRAGYA SAINI) पुत्री मोहन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

मोहन पुत्र श्री प्रकाश चंद
निवासी–ग्राम शांतरशह, दौलतपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249402.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 6886XXXX2653 में त्रुटिवश मेरा नाम मंगल सिंह कुंवर सिंह रावत (MANGAL SINGH KUNWAR SINGH RAWAT) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रावत मंगलसिंह कुवरसिंह (RAWAT MANGALSINGH KUWARSINGH) है जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष–2005 सीट नं–B318686 एवं स्थानांतरण सर्टिफिकेट रजि.सं. 761 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे रावत मंगलसिंह कुवरसिंह (RAWAT MANGALSINGH KUWARSINGH) पुत्र कुवर सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रावत मंगलसिंह कुवरसिंह
(RAWAT MANGALSINGH KUWARSINGH)
पुत्र कुवर सिंह रावत
निवासी 129, खदरी खडकमाफ, टिहरी विस्थापित कॉलोनी, ऋषिकेश एस. एन टेम्पल, एस एन मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड 249204

सूचना

विवाह से पूर्व मेरा नाम पूनम गैरोला पुत्री श्री अम्बिका प्रसाद गैरोला था जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष 2017 अनुक्रमांक 5313952 एवं पेन कार्ड नं0 DSFPG0619K में भी दर्ज है। लेकिन विवाह के उपरान्त मैनें अपना नाम पूनम गैरोला से बदलकर पूनम सेमवाल कर लिया था। जोकि मेरे ई–मतदाता पहचान पत्र संख्या YYZ0775155 में भी दर्ज है। लेकिन मेरा मेरे पति श्री आलोक सेमवाल से न्यायालय, अपर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विकासनगर देहरादून के मूल वाद संख्या 102 वर्ष 2025 सी0एन0आर0 नं0 UKDD–11–000–230–2025 के अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। इसलिए मैं अपना पुनः पूर्व नाम पूनम सेमवाल से बदलकर पूनम गैरोला करना चाहती हूँ। भविष्य में मुझे पूनम गैरोला (POONAM GAIROLA) पुत्री श्री अम्बिका प्रसाद गैरोला के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पूनम गैरोला (POONAM GAIROLA)
पुत्री श्री अम्बिका प्रसाद गैरोला
निवासी–पश्चिमीवाला, तहसील विकासनगर,
जिला–देहरादून।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के स्कूल रिकोर्ड में त्रुटिवश उसका नाम ADHYA गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम AADHYA BHARDWAJ है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र पंजी B202405901710000834 व पुत्री के आधार कार्ड नं0 6430 8134 0774 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे AADHYA BHARDWAJ D/O SANJAY BHARDWAJ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

SANJAY BHARDWAJ
निवासी माँ सरस्वती कॉलोनी नकौंदा देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 991447502230 में त्रुटिवश मेरा नाम बलवीर सिंह गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम बलबीर सिंह है जोकि मेरे वोटर आईडी कार्ड संख्या ZMV0013441 व मेरी धर्मपत्नी कंचनबाला के पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या UCI/162/22453 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे बलबीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बलबीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह
नि0 9/3 विंग नंबर 07 प्रेमनगर, देहरादून,
प्रेमनगर देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे NIOS हाईस्कूल वर्ष 2016 अनुक्रमांक 340140152037 एवं NIOS इण्टरमीडिएट वर्ष 2018 अनुक्रमांक 340140163516 में त्रुटिवश मेरी माता का नाम MADHU CHAUHAN एवं पिता का नाम HIRA SINGH CHAUHAN गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी माता का वास्तविक नाम MADI DEVI एवं पिता का वास्तविक नाम HEERA SINGH है। जोकि मेरे स्थायी निवास प्रमाण–पत्र संख्या 1004001301063 एवं मेरी माता के आधार कार्ड नं0 734633257284 एवं पिता के आधार कार्ड नं0 992836483727 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे माता पिता को सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

RADHIKA CHAUHAN D/o HEERA SINGH
निवासी–हाउस नं. 22, प्यूनल, पो0ओ0– मून्धोल,
जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड–248199

सूचना

मेरे NIOS हाईस्कूल वर्ष 2016 अनुक्रमांक 340140152041 एवं NIOS इण्टरमीडिएट वर्ष 2018 अनुक्रमांक 340140163517 में त्रुटिवश मेरी माता का नाम MADHU CHAUHAN एवं पिता का नाम HIRA SINGH CHAUHAN गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी माता का वास्तविक नाम MADI DEVI एवं पिता का वास्तविक नाम HEERA SINGH है। जोकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 02/2006 एवं मेरी माता के आधार कार्ड नं. 734633257284 एवं पिता के आधार कार्ड न0 992836483727 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे माता पिता को सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ASHISH CHAUHAN S/O HEERA SINGH
निवासी–हाउस नं. 22, प्यूनल, पो0ओ0– मून्धोल,
जिला–देहरादून, उत्तराखण्ड–248199

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 9042 3514 2395 में त्रुटिवश उसका नाम RYTHEM RATHORE गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रिद्धिम (RIDHIM) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजी 36710 व स्थाई निवास प्रमाण–पत्र सं0 UK25ES0100648548 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को रिद्धिम (RIDHIM) पुत्र रीता देवी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रीता देवी पत्नी श्री संजीत
निवासी गाँव मुंडेट पी0ओ0 मंगलौर शहर तह0 रुड़की
जिला– हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 2205 XXXX 5855 एवं पेन कार्ड नं0 XXXXXX891F में मेरा नाम रंजना (RANJNA) दर्ज हैं। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम रंजना (RANJNA) से बदलकर रंजना एडवीन (RUNJANA EDWIN) कर लिया है। भविष्य में मुझे रंजना एडवीन (RUNJANA EDWIN) पत्नी स्व0 एडवीन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रंजना (RANJNA) (मौजूदा पुराना नाम)
पत्नी स्व0 एडवीन सिंह
निवासी–57/5A लेन नं0 08, टर्नर रोड़,
ओवरसिस बैंक क्लेमेंटाउन रोड़, देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

प्रार्थी ने अपना नाम भीमसेन से बदलकर भीमसेन गुप्ता करते हुए उसे आधार कार्ड सं0 779861996247 में दर्ज करा दिया है। भविष्य में मुझे भीमसेन गुप्ता के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(भीमसेन गुप्ता)
निवासी– 3/18, एकता विहार,
पोस्ट– कण्डोली, सहस्रधारा रोड,
देहरादून।

सूचना

प्रार्थी ने अपना नाम अटल विहारी से बदलकर अटल बिहारी बाजपेयी करते हुए उसे आधार कार्ड सं0 334456257885 में दर्ज करा दिया है। भविष्य में मुझे अटल बिहारी बाजपेयी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

(अटल बिहारी बाजपेयी)
निवासी– लेन नं0–3, एकता विहार,
पोस्ट– कण्डोली, सहस्रधारा रोड,
देहरादून।

सूचना

मैं दीपा देवी दुदपुड़ी पत्नी NO.68400043 Ex. L-NK स्व0 महेशानन्द दुदपुड़ी निवासी ग्राम सैंज मल्ला, पोस्ट डाडामंडी जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। पिन– 246124 घोषणा करती हूं कि मेरे पति के पीपीओ नंबर 240558607432 में DEEPADA PADI एंव SSA No.240558607432/1695 812/A1 में DEEPDA DEVI गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम DEEPA DEVI DUDPURI है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानि मेरे ही हैं।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दीपा देवी दुदपुड़ी
पत्नी NO.68400043 Ex.L-NK स्व0 महेशानन्द दुदपुड़ी
निवासी ग्राम सैंज मल्ला, पोस्ट डाडामंडी जिला पौड़ी
गढ़वाल, उत्तराखंड। पिन–246124

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 4367 XXXX 5704 में त्रुटिवश मेरा हिन्दी में नाम संजीत व अंग्रेजी में नाम (SANGEET) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम संजीत कुमार (SANJEET KUMAR) है। जो मेरे डी0एल0 नं0 UK-1420060070394 व मेरे पुत्र वंश कुमार के हाईस्कूल रोल नं0 26012467 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे संजीत कुमार (SANJEET KUMAR) पुत्र श्री मेघराज सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संजीत कुमार (SANJEET KUMAR) पुत्र श्री मेघराज सिंह
निवासी रामपुर जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 3399 6813 3540 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रियांशु (Priyanshu) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रियांश थापा (Priyansh Thapa) है। जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक 25116688 व जन्म प्रमाण पत्र पंजी. सं. B-20080910336 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे प्रियांश थापा (Priyansh Thapa) पुत्र श्री लक्ष्मण के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रियांश थापा (Priyansh Thapa) पुत्र श्री लक्ष्मण
निवासी सभावाला देहरादून, उत्तराखंड।

सूचना

मेरी एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 272041142 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम Susutri गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शिवन्या सैनी (Shivanya Saini) है। जो मेरे जन्म प्रमाण–पत्र पंजी सं0 B-2019:5-90069-005075 व हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25124910 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे शिवन्या सैनी (Shivanya Saini) पुत्री श्री रविन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाएं।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शिवन्या सैनी (Shivanya Saini) पुत्री श्री रविन्द्र कुमार
निवासी–सलेमपुर राजपुतान रुड़की जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 394058967824 में त्रुटिवश उसका हिन्दी एवं अग्रेजी में नाम यशस्विनी उनियाल (YASHASWINI UNIYAL) के स्थान पर अश्रिनी उनियाल (ASHWINI UNIYAL) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का हिन्दी एवं अग्रेजी में सही नाम यशस्विनी उनियाल (YASHASWINI UNIYAL) है। जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. 20130404547 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को यशस्विनी उनियाल (YASHASWINI UNIYAL) पुत्री श्री प्रवीण उनियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

प्रवीण उनियाल
निवासी– बजरावाला रोड, उत्तराँचल कम्प्यूटर सेंटर, मधुर विहार, बन्जारावाला माफी, देहरादून–उत्तराखण्ड–248001

सूचना

मेरी एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 271519786 में मेरा घरेलू नाम YESPAL दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम पप्पू (PAPPU) है। जोकि मेरे आधार कार्ड नं0 6692 5539 0750 व पेन कार्ड नं0 FFPPP7030N में भी दर्ज है। YESPAL उर्फ पप्पू (PAPPU) ये दोनों मेरे ही नाम है। भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पप्पू (PAPPU) पुत्र बरीक
निवासी–टांडा हसनगढ खेडी शिकोहपुर खेरी
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 4895 XXXX 9415 में त्रुटिवश उसका नाम आक्षी (AKSHI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आशी सैनी (ASHI SAINI) है। जो पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र पंजी सं0 B202405900690010416 व स्थाई निवास प्रमाण–पत्र पंजी सं0 UK25ES0100275399 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को आशी सैनी (ASHI SAINI) पुत्री श्री अरूण कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरूण कुमार
निवासी– मंगलौर तोवन जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नंबर 490539952418 में त्रुटिवश उसका अंग्रेजी में नाम ARNIMA के स्थान पर ARMINA गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का अंग्रेजी में सही नाम ARNIMA है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B2025003920000004 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम ARNIMA D/O DINESH SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

DINESH SINGH
निवासी–13, ब्रह्मखाल मथाली, उत्तरकाशी,
कोटधार उत्तराखंड –249152

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 9583 8593 4791 में त्रुटिवश इंग्लिश में नाम KIHER SINGH के स्थान पर KEHAR SINGH गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा इंग्लिश में वास्तविक नाम KIHER SINGH है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 1938920 व मेरे पुलिस के रिकोर्ड में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे KIHER SINGH पुत्र स्व0 गोवर्धन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

KIHER SINGH पुत्र स्व0 गोवर्धन
निवासी 14 न्यू आदर्श नगर सोलानी ग्रीन्स मलकपुर
लतीफपुर रुड़की जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के वर्ष 2024 इण्टरमीडिएट ENROLLMENT NO. 340257233046 में त्रुटिवश उसका नाम ADITYA SINGH BARTWAL गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम ADITYA SINGH है। जोकि पुत्र के वर्ष–2022 हाईस्कूल अनुक्रमांक 25108881 एवं पुत्र के आधार कार्ड नं. 625228679734 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को ADITYA SINGH S/o MAHENDRA SINGH BARTWAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

MAHENDRA SINGH BARTWAL
निवासी–8/7, सिदारथ विहार, कडोली, देहरादून,
उत्तराखण्ड– 248001.

सूचना

मेरे स्व0 पति PADAM PRAKASH के भारतीय स्टेट बैंक के खाता नं0 1090171210–4 नॉमिनी में मेरा नाम सरोज बडोनी (SAROJ BADONI) दर्ज हैं। जबकि मेरे आधार कार्ड नं0 8864 1331 3755 व पेन कार्ड नं0 EMTPB3799C में मेरा नाम सर्वेश्वरी देवी (SARVESHWARI DEVI) दर्ज है। सरोज बडोनी (SAROJ BADONI) उर्फ सर्वेश्वरी देवी (SARVESHWARI DEVI) ये दोनों मेरे ही नाम है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सर्वेश्वरी देवी (SARVESHWARI DEVI)
पत्नी स्व0 श्री PADAM PRAKASH
निवासी–लेन नं0 05, कैनरा बैंक बद्री केदार एन्क्लेव
इन्दरपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं गीता यादव मेरे नाबालिग पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र सं0 B20170703403 व आधार कार्ड नं0 4628 8184 0110 में उसका नाम सम्राट यादव (SAMRAT YADAV) पुत्र श्री शशांक यादव दर्ज है। लेकिन मेरा अपने पति शशांक यादव से न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब दे0दून मूलवाद सं0 457/2019 दिनांक 17/02/2020 के अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। मैंने पुनः विवाह श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रीत्तम सिंह शर्मा से कर लिया है। जो विवाह प्रमाण–पत्र MR-UKUCC2549000024581 में भी दर्ज है। मेरे पति श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा मेरे पुत्र सम्राट यादव का गोदनामा दिनांक 07.05.2025 के तहत गोद ले लिया गया है। अतः मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम सम्राट यादव (SAMRAT YADAV) से बदलकर सात्विक शर्मा (SATVIK SHARMA) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र पंज स0 B202505901700006502 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सात्विक शर्मा (SATVIK SHARMA) पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गीता यादव पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा
निवासी 2 लेन नं0 04 एकता एन्क्लेव लोवर नथनपुर
नेहरूग्राम देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण सं 2598/2006 दिनांक 22–08–2006 में मेरा नाम अंशु कुमार कश्यप दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम अंशु कुमार कश्यप से बदलकर कृष्णा कश्यप (KRISHNA KASHYAP) कर लिया है। जो मेरे आधारकार्ड नं. 9262 9004 2581 व हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 24004160 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कृष्णा कश्यप (KRISHNA KASHYAP) पुत्र स्व सुनील कश्यप के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

कृष्णा कश्यप (KRISHNA KASHYAP)
पुत्र स्व सुनील कश्यप
निवासी–हाउस नं. 275, राही होटल के पास प्रोजेक्ट
कॉलोनी मायापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 322610189995 में त्रुटिवश मेरा नाम हंसराज (HANSRAJ) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम HARSH KUMAR है जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष–2024 अनुक्रमांक 25129222 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे HARSH KUMAR पुत्र श्री शिव चरण सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

HARSH KUMAR पुत्र शिव चरण सिंह
निवासी–ग्राम–तानशिपुर, जिला–हरिद्वार,
राज्य–उत्तराखण्ड–247656.

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 9133 7165 2083 में त्रुटिवश मेरा नाम निगार (NIGAR) तथा पति का नाम काजिम गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शाहजहां (SHAHAJAHAN) तथा पति का वास्तविक नाम काज़िम खान (KAZIM KHAN) है। जो मेरे परिवार रजिस्टर की नकल व पुत्र मौ0 कासिफ खान के जन्म प्रमाणपत्र सं0 B202505077160000173 में भी दर्ज हैं भविष्य में मुझे (SHAHAJAHAN) पत्नी काज़िम खान (KAZIM KHAN) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(SHAHAJAHAN)
पत्नी काज़िम खान (KAZIM KHAN)
निवासी लन्ढौरा जौरासी मुस्त, हरिद्वार, उत्तराखंड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/294–भाग 8–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।